In so far as Primary School teachers in Delhi are concerned, there will be only one pay scale as mentioned above.

With regard to the other categories of teachers, the pay scales will be as recommended by the Third Pay Commission.

As I have already stated earlier, on the basis of the pay fixation formula recommended by the Third Pay Commission and the scales of pay now finally approved by the Government, the existing teachers *i.e.,* the teachers who had been appointed prior to 1-1-1973 v/ould, by a judicious exercise of options available to them, find the revised scales of pay more favourable than even the 1971 scales of pay.

Government have decided to increase the number of selection grade posts from 15 per cent of the permanent posts in each category to 20 per cent of the permanent as well as temporary posts which have been in existence for three years or more. This will give the benefit of selection grade to a larger number of teachers. There will be no selection grade for the posts of Headmasters of High Schools, Vice-Principals of Higher Secondary Schools as well as Principals of Higher Secondary Schools.

The decision already taken by the Delhi Administration to introduce the new pattern of school education (10 + 2) and to reorganise the curricula at all stages of education is likely to lead to further widening of promotional avenues for teachers.

The revised pay scales will be introduced in the other Union Territories and organisations on Central scales of pay, such as Andaman and Nicobar Islands, Pondi-cherry, Lakshadweep, Goa. Daman, and Diu and the Central Schools.

I do hope that the teachers would welcome these decisions of the Government and call off their agitation immediately and resume their duties.

Taking into account the undue hardship experienced by the candidates who ate to take the Delhi Higher Secondary Examination, steps are being taken by the Central Board of Secondary Education to hold' the examination as early as possible.

1 P.M.

THE BUDGET (GUJARAT) 1975-76— *General Discussion*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We can go to the Gujarat Budget now. I would suggest that those who want to speak on Gujarat may speak on the Budget and the other Bills can be passed . . .

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : There are two separate propositions, one is the Budget and the others are Bills. I am not objecting to what you say. You can save time but this practice should be given up. We know we are not vigilant and careful about the way in which we are conducting our House but how can you say that we should not speak . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Bhupesh Gupta, listen to me. What I am suggesting is that all those who want to make speeches may do so on the Budget and then the Bills can be taken up separately.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, I got you quite all right. I heard you very clearly, this is what precisely you said and this is what precisely I am objecting to. The Budget is generally discussed. Suppose, somebody wants to pick up a particular thing and say something, why should it relate to other items? These are two separate items and should be taken up as two separate items. You can say, here are all the Bills, speak on them together. You can shorten the discussion. You can say whatever you like but Budget is a matter for general discussion and the Bills are to be discussed in their own way. Suppose one member of a party wants to talk about politics of Gujarat and the other member of the party wants to speak on the Bill . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Well, Mr. Bhupesh Gupta, whichever procedure you want to follow we will follow. Unnecessarily you will be wasting time.

SHRI BHUPESH GUPTA : It is not the question of wasting time. Sometimes it can be a waste of time but not necessarily always. What I say is, do not abandon the procedure. Do not throw the baby with the bath water.

AN HON'BLE MEMBER : Sir, we have followed what Mr. Bhupesh Gupta said.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : There is no dispute on that. We will be sitting through lunch to complete the business.

श्री इन्द्रदीप सिंह (बिहार) : उप-सभापति महोदय, गुजरात में राष्ट्रपति शासन का एक साल का काल समाप्त हो गया और एक साल बाद आज जो परिस्थिति देश के सामने और इस सदन के सामने है उसमें दो प्रश्न विचारर्थ उपस्थित होते हैं।

IThe Vice-Chairman (Shri Jagdish Prasad Mathur) in the Chair]

पहला प्रश्न यह है कि जिन शक्तियों ने गुजरात विधान सभा को तोड़ करके यह स्थिति उत्पन्न कराई और उस समय जो जनता के सामने उन्होंने वायदे किये थे क्या वे वायदे पूरे हुए और दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार ने उस समय जो वायदा किया था कि शीघ्रातिशीघ्र हम चुनाव कराएंगे और फिर से संसदीय प्रणाली की स्थापना करेंगे, तो क्या सरकार ने यह वायदा पूरा किया ? इन दोनों प्रश्नों को मैं आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं ।

उप-सभाध्यक्ष, महोदय मुझे स्मरण है, गुजरात का आन्दोलन जब चला था तब मंहगाई की, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की और विद्यार्थियों के दमन की बड़ी शिकायत थी और इन तात्कालिक प्रश्नों को लेकर वहां का आन्दोलन आरम्भ हुआ था। इस आन्दोलन का बहाना बनाकर कतिपय राजनैतिक तत्वों और दलों ने उस आन्दोलन में एक राजनैतिक मांग यह भी जोड़ दी थी कि गुजरात विधान सभा को भंग करो और कुछ इस प्रकार का वातावरण पैदा किया गया था कि मानों गुजरात विधान सभा को भंग करने से यह सवाल हल हो जाएंगे। परिणामस्वरूप गुजरात विधान सभा भंग हुई... (*Interruptions*) मैं तो जहां हूं वहीं से बोल रहा हूं। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिंहावलोकन करने का आपका और हमारा दोनों का अधिकार है तो एक साल बीत जाने के बाद इस सदन में और सदन के बाहर भी हमें गम्भीरता पूर्वक इस प्रश्न पर गौर करना है कि क्या मंहगाई के खिलाफ आन्दोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन, संगठित विधान-सभा को भंग करके सफल हो सकता है ? लेकिन गुजरात का कटु अनुभव हमें बतलाता है कि विधान सभा भंग होने के बाद भी मंहगाई और भ्रष्टाचार का जो अभिशाप है वह कम नहीं हुआ। श्रीमन् इसका कारण बहुत स्पष्ट है। मंहगाई और भ्रष्टाचार विधान सभा या संसद के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं। मंहगाई और भ्रष्टाचार की जननी वह सामाजिक व्यवस्था है जिसको हम पूंजीवादी व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं मंहगाई और भ्रष्टाचार पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के अभिशाप हैं। हम यह नहीं कहते कि पूंजीवाद को तुरन्त तोड़ देना संम्भव है, लेकिन मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंहगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर संघर्ष तभी चलाया जा सकता है जब पूंजीवाद के शोषक और भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ संघर्ष किया जाय। बदकिस्मती से गुजरात में जो आन्दोलन चला था, और जो पहले विद्यार्थी आन्दोलन था, निहायत ईमानदारी के साथ दुस्सह परिस्थितियों के खिलाफ विद्यार्थी समाज ने उसे उठाया था। और जो वहां पर सरकार थी उसके दमन से, उसके अत्याचार से ऊब कर उन्होंने मांग की थी कि गुजरात विधान सभा को भंग करो। विद्यार्थियों की यह मांग पवित्र थी, उनका क्रोध भी पवित्र था, मेरे मित्र जोशी जी का क्रोध भी पवित्र था, हमारे भी जो लोग थे उनका क्रोध पवित्र था। लेकिन मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ तत्वों ने जिन्होंने गुजरात आंदोलन को अपनी राजनीति का हथकंडा बनाया, उनके दिल में भी वही पवित्र क्रोध भ्रष्ट आचरण के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, शोषण करने वालों के खिलाफ था ? क्योंकि सामाजिक दृष्टि से भ्रष्टाचार और महंगाई की जड़ पूंजीवादी व्यवस्था में है, किसी विधान सभा में नहीं है, किसी संसद में नहीं है।

इसलिये उपसभाध्यक्ष महोदय, साल भर बाद इस पूरी परिस्थिति पर गौर करके देश को इस निष्कर्ष पर पहुंचने का अवसर आया है कि गुजरात आंदोलन में कुछ राजैतिक शक्तिओं का जो यह स्वार्थी था वह पहलू किसी भी तरह से श्लाघनीय नहीं कहा जा सकता। मैं आपको इसका एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं ; एक संस्था है वहां पर—हमारे मित्र उमाशंकर जोशी जी उससे बहुत परिचित होंगे—गुजरात विद्यापीठ मुझे जान कर आश्चर्य हुआ कि वहां मोरारजीभाई देशाई शिक्षा शास्त्री माने जाते है, एजुकेशनिस्ट माने जाते हैं, और वे गुजरात विद्यापीठ के चांसलर है और श्रीराम लाल पारिख उसके वाइस चांसलर हैं। गुजरात में जहां इतने इतने एजुकेशनिष्ट हो वहां मोरारजी भाई इसके इंचार्ज हों, इसके चांसलर हों, यह बात बहुत आश्चर्यजनक है; खैर वह हैं। वहां पर 72 दिनों से विद्यार्थियों की हड़ताल चल रही है – विद्यार्थी और शिक्षक दोनों आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां के अधिकारियों ने तुलनात्मक धर्मशास्त्र के शिक्षक डा. दूरानी को बरखास्त कर दिया है बिना किसी वजह के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं उनको फिर से वहाल किया जाए शिक्षक मांग कर रहे हैं उनको फिर से बहाल किया जाए और विद्यार्थियों और शिक्षकों की मांग है कि पिछले 10 के साल गुजरात विद्यापीठ के अकाउण्टस् पेश किए जाएं। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 साल से उस विद्यापीठ का कोई अकाउन्ट पेश नहीं हुआ युनिवर्सिटी ग्राण्टस् कमीशन पैसा उनको देती है तो उसका हिसाब किताब जरूर रखा जाना होगा। लेकिन उसका कोई लेखाजोखा सामने नहीं। और, मोरारजी देसाई जो अभी गुजरात में आंदोलन चला रहें हैं प्रजातन्त्र की स्थापना के लिये वे गुजरात विद्यापीठ में प्रजातन्त्र के विरोधी है, वे गुजरात विद्यापीठ में प्रजातंत्र स्थापित नहीं होने देना चाहते, वहां के प्रशासन में वहां के विद्यार्थियों को, शिक्षकों को कोई अधिकार देना नहीं चाहते।

श्री उमाशंकर जोशी (नाम निर्देशित) : आपको पता नहीं, परसों समाधान हो गया।

श्री इन्द्रदीप सिंह : समाधान हो गया तो बडी अच्छी और खुशी की बात है लेकिन समाधान होने के बाद भी मैं चाहूंगा कि मोरारजी देशाई जैसे व्यक्ति को वहां पर चांसलर नहीं रहना चाहिए। मेरे मित्र उमाशंकर जोशी जी चांसलर बनाए जाएं, मैं इसका स्वागत करूंगा, लेकिन मोरारजी भाई चांसलर बने रहेंगे तो, उपसभाध्यक्ष महोदय मुझे माफ करेंगे शेक्सपीयर की एक लाइन है :

If he, compact of all jars, grows musical, we shall have discord in the atmosphere.

इसलिये मोरारजी भाई अगर शिक्षा शास्त्री बन जाएं तो– we shall have discord in the atmosphere. वायुमण्डल में गड़बड़ी पैदों हो जायेगी इसलिये उनको वहां उस पद से हटना चाहिए।

सरकार की नीति के बारे में मेरे दिमाग में एक प्रश्न है।

जिस समय गुजरात विधान सभा भंग हुई उसके बाद से लगातार महीनों तक सरकारी पक्षकी तरफ से यह ऐलान किया जाता रहा है कि हम शीघ्रातिशीघ्र गुजरात में चुनाव कराएंगे। जैसे ही क्षेत्रों का परिसीमन हो जाएगा चुनाव करा लेंगे, जैसे ही मतदाता सूचियां तैयार हो जाएंगी करा लेंगे। यह काम जब हो गया, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा हम चुनाव कराने के लिये तैयार हैं। तब सरकार ने यह महसूश किया कि गुजरात में बड़ा अकाल पड़ा है और इसलिये वहां पर चुनाव नहीं कराये जा सकते है। श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अकाल वहां पर अकस्मात नहीं पड़ा, वहां पर अकाल कई महीनों से है और पिछले साल भी गुजरात में अकाल पड़ा था और वहां पर महीनों से रिलीफ का काम चल रहा था अब अकाल के बाद भी सरकार कह रही थी कि इस साल जनवरी या फरवरी में वहां चुनाव कराये जा सकते है। मैं समझता हूं कि सहकार अपना राजनैतिक स्वार्थ साधने के लिए अब उस तरह की बात कह रही है। सम्भवत गुजरात में चुनाव

[श्री इन्द्रदीप सिंह]

न कारये कोई दूसरा कारण है और अकाल प्रधान कारण नहीं है। अगर अकाल प्रधान कारण हुआ है इसकी बात तो उसका नाम पहिले से ही लिया जाता ।

मैं आपसे से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे गुजरात में विभिन्न दलों और विभिन्न व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला है; और वहां पर आम राय है कि वहां पर शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जाये। अब मैं सरकार से यह चाहता हूं कि वह इस बारे में दो टूक ऐलान कर दे कि वहां पर वह कब चुनाव करायेगी ? सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि वहां पर जल्द से जल्द चुनाव कराये जायगें तो मैं यह जानना हूं कि यह कब आयेगी ? क्या आप वहां पर अक्टूबर में चुनाव करायेंगे या फिर अगले साल फरवरी में करायेंगे ? इस तरह से वहां की जनता को किसी तरह से दुविधा की स्थिति में रखना उचित नहीं है और इस बारे में साफ बात का ऐलान हो जाना चाहिये ।

तीसरी बात में यह निवेदन करना चाहता हैं कि इस समय गुजरात में अकाल सहायता कार्य चल रहा है । जो रुपया उसमें खर्च हो रहा है वह करीब 26 करोड़ के हैं और यह जो राशि उसे मैं पर्याप्त नहीं समझता हूं क्योंकि आज जो पैसे का मूल्य हो गया है और जिस तरह से महंगाई बढ़कर चीजों की कीमतें बढ़ गई है, उसके अनुपात में यह राशि बहुत कम है मुझे अकाल सहायता कार्य करने का अनुभव है क्योंकि 1967 में जब बिहार में संयुक्त मोर्चे की सरकार थी तो मैं वहां पर मंत्री था और उस समय हम लोगों ने लगभग 65-70 करोड़ रुपया 1967 में बिहार में अकाल पीड़ित की सहायता में खर्च किया था । गुजरात में जो विपत्ती आई है वह बिहार से कम नही है, जहां तक मेरा अनुमान है । यह ठीक है कि गुजरात की जनसंख्या कम है, लेकिन गुजरात में जो अकाल पीड़ित क्षेत्र हैं, जहां पर दो तिहाई गांव आकाल पीड़ित या अभाव पीड़ित है । जहां पर 12 हजार पीडित-क्षेत्र घोषित कर दिये गये हैं, वहां के लिये इतनी राशी बहुत कम मालूम देती है। और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले प्रभावित क्षेत्र के लिये यह राशि जो बजट में रखी गई है वह बहुत कम है । मेरे ख्याल से यह राशि पर्याप्त नहीं है।

मुझे इस बारे में व्यक्तिगत तर्जबा है, क्योंकि वहां पर जो काम चलाया जा रहा है उसमें 100 वर्ग फुट मट्टी निकालने के लिये तीन रुपया दिया जाता है । एक मजदूर अगर मजबूत हो, बहुत कमजोर शरीर का नहीं, तो वह दिन भर में मेहनत करके अधिक से अधिक तीन रुपया अर्जित कर सकता है। आज के जमाने में अगर कोई मिट्टी काटने वाला दिन भर काम करे और तीन रुपया कमाये और वह बाजार में जाकर क्या खरीद सकेगा जबकि आटा दो रुपये किलो बिक रहा है और किस तरह से वह अपनी तथा अपने घरवालों की परवरिश कर सकता है ? इसलिये मुझे याद है कि बिहार में उस जमाने में यानी 1967 में हम लोग तीस रुपया हजार फुट के हिसाब से पेमेंट करके थे। आज तो 1974-75 का साल है और इन पांच सात सालों में जबकि चीजों के दाम बहुत ऊंचे चले गये है और पैसे के भी कीमत कम हो गई है । इसलिये वहां के मजदूरों को जो इस समय पेमेंट किया जाता है वह पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि गुजरात रिलीफ में जो मजदूरों को पेमेंट किया जाता है, वह आज की बड़ी हुई कीमतों को देखकर तय किया जाना चाहिये । मैंने एक मीटिंग में यह सुझाव दिया था कि पी. डब्ल्यू. के काट्रेक्टरों को जो रेट मिट्टी काटने के लिये दिया जाता है उसको 90 प्रतिशत रिलीफ स्कीम में जो फार्मूला है, जिस को फैमिन कोड में भी मान लिया गया है, उस हिसाब से इनको पेमेंट किया जाना चाहिये ।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन रिलीफ स्कीमों में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हे अपना समान खरीदने के लिये कई कई मील दूरी पर जाना पड़ता है । इसलिये वहां पर समान के डिपो होने चाहिये ताकि जहां पर मजदूर काम करते हों वहां पर ही वे आसानी के साथ अपना सामान खरीद सकें और उन्हे अपना सामान खरीदने के लिये दूर न जाना पड़े ।

पांचवीं बात, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल सहायता का काम तो चल रहा है, लेकिन कुछ दूसरे मुद्दे जो अत्यन्त आवश्यक हैं उनकी तरफ से सरकार का ध्यान, लगता है, हटा हुआ है। अभी 12 मार्च को डांग जिले के अहवा नामक स्थान पर आदिवासियों ने प्रदर्शन किया और सभा की आदिवासियों की मांग यह है कि जो जमीन वे पहले से जोतते आ रहे हैं उस जमीन पर उनको जोतने का हक मिल जाये, उनको आकूपेन्सी राइट मिल जाय, जिन आदिवासियों के पास जमीन नहीं है उनको ज्यादा जमीन अलाट की जाय। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं स्मरण दिलाऊं कि शासक दल की तरफ से नरोरा में एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें यह घोषणा की गई थी कि 15 फरवरी तक देश में जितने भूमिहीन परिवार हैं या कम जमीन वाले गरीब किसान परिवार हैं उनको बसने के लिये जमीन दे देंगे। 15 फरवरी बीत चुकी। हम लोग आशा करते थे कि सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट दी जायेगी कि इस पर कहां तक अमल हुआ। गुजरात में कहां तक इस पर अमल हुआ, कहां तक गुजरात में भूमिहीनों को बसने के लिये जमीन दी गई, इस पर सरकार की तरफ से कोई विशेष बयान दिया जायेगा, ऐसी हम आशा करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदिवासियों का जो आन्दोलन चल रहा है वह बसने की जमीन के लिये है और जोतने की जमीन के लिये भी है।

आदिवासियों की एक और मांग है। महाजनों ने उनकी बहुत सारी जमीन खरीद ली है। वह जमीन वापस दिलाने का आन्दोलन गुजरात में आदिवासियों द्वारा चलाया जा रहा है और दूसरे प्रान्तों में भी चलाया जा रहा है। गुजरात में आदिवासियों और कुछ दूसरे लोगों के बीच अक्सर तनाव की स्थिति पैदा हो जाया करती है और मारपीट हो जाया करती है। तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि भूमिहीनों को जमीन देने के सम्बन्ध में आदिवासियों की जो अपहृत जमीन है, जो उनसे एलियनेटेड लैंड है उसको वापस दिलाने के सम्बन्ध में, सरकारी बंजर जमीन को तोड़कर भूमिहीनों को देने के सम्बन्ध में, आदिवासी जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं उस पर उनका कबजा स्वीकार करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। इस सबके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

श्रीमती कुमुदबेन मणिशंकर जोशी (गुजरात): उपासभाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं गुजरात के बारे में बोल रही हूं तब मैं बहुत दुखी दिल से बोल रही हूं। गुजरात की जनता पिछले तीन सालों से प्राकृतिक समस्याओं का सामना कर रही है। 1972 में गुजरात में अकाल हुआ, 1973 में अतिवृष्टि हुई, 1974 में फिर अकाल काफी जोर से गुजरात में हुआ आज गुजरात की जनता प्राकृतिक समस्याओं से परेशान है, बड़ी कठिनाई से उसका मुकाबला कर रही है। ऐसी हालत में गुजरात के राजनीतिक खिलाड़ियों ने गुजरात को आन्दोलन का स्टेज बनाया हुआ है। पिछले साल गुजरात की सरकार को नवनिर्माण के आन्दोलन के नाम से तोड़ा। इस नवनिर्माण अन्दोलन ने गुजरात को क्या-क्या दिया है वह गुजरात की जनता भूलने वाली नहीं है। गुजरात के छात्र आज पढ़ते नहीं हैं और पढ़ाने भी नहीं देते है। यह है गुजरात की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या। गुजरात की जनता आज भी अकाल की परिस्थितियों से बहुत परेशान है। मैं कुछ आंकड़े सदन के समाने देना चाहती हूं। गुजरात में गरीब 13 हजार गांव अकालग्रस्त हैं। वहां 7 लाख लोगों को सरकार की ओर से काम दिया जा रहा है। 24300 लोग बूढ़े और अपंग हैं। उनको सरकार अपनी ओर से सहायता दे रही है। हम लोग जनता की परेशानियों से बहुत चिन्तित हैं। भारत सरकार, गुजरात सरकार और जनता भी उसका मुकाबला कर रही है। ऐसे में जो लोग सत्ता के पीछे पड़े हुए हैं वे फिर विधान सभा के चुनाव की मांग कर रहे हैं। 13 हजार गांवों में अकाल छाया हुआ है, दिन प्रतिदिन अकाल की परिस्थिति शोचनीय होती जा रही है, सरकार अपनी सारी शक्ति इस काम से हटा कर चुनाव में लगाएगी तो गुजरात की पीड़ित जनता का क्या होगा। यह सब सोचने

[श्रीमती कुमुदबेन मणिशंकर जोशी]

का इनके पास समय नहीं है क्योंकि ये लोग तो सत्ता के पीछे पड़े हुए हैं ।

मैं आप के माध्यम से उपसभाध्यक्ष महोदय भारत सरकार के सामने तीन चार मुद्दे रखना चाहती हूं । गुजरात में हर साल कहीं न कहीं बाढ़ की वजह से या पानी की कमी की वजह से या सूखे की वजह से किसान को मुसीबत झेलनी पड़ती है और इस के लिये मैं सरकार को तीन सुझाव देना चाहती हूं । गुजरात के किसानों को छोटी सिंचाई योजनाओं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा या चेक डैम्स के द्वारा पानी की सुविधा मिलनी चाहिये और अगर आप गुजरात के किसान को पानी देंगे तो वह जमीन से सोना उगलवा लेगा । वह इतना मेहनती है और उस को पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान भी है । इस के अतिरिक्त गुजरात में जब पानी अच्छा हो जाता है तो रासायनिक खाद की कमी हो जाती है। तो मैं भारत सरकार से विनती करना चाहती हूं कि गुजरात में गोबर गैस प्लान्ट की योजना अच्छी तरह से चल रही है। ग्रामोद्योग कमीशन ने उस में काफी अच्छा काम किया है और वह अच्छी दिलचस्पी उस में ले रहा है । लेकिन अगर गुजरात के किसान को वह नहीं मिल पाती है तो पंचवर्षीय योजना में आप ने जो गोबर गैस की योजना रखी है उस की सुविधा गुजरात के किसानों को जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए इस का आप प्रयत्न करें तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है । गुजरात का कृषि विश्वविद्यालय गुजरात के किसानों के मामले में काफी दिलचस्पी ले रहा है और उस के लोग उन के काम में लगे हुए हैं तो मैं भारत सरकार से विनती करती हूं कि वहां का कृषि विश्वविद्यालय जो काम कर रहा है उस के लिये उस को पूरी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए । जब तक उस विश्वविद्यालय को आप पूरी आर्थिक मदद नहीं देंगे तब तक कृषि विश्वविद्यालय अपने को पूरी तरह डवलप नहीं कर पायेगा और उस की वजह से गुजरात के किसानों को भी मुश्किल रहेगी ।

आज जब मैं गुजरात की बात कर रही हूं तो उपसभाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं गुजरात की जनता को भारत सरकार को और गुजरात के राज्यपाल को धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस कठिन परिस्थिति में उन सब ने मिलकर एक रास्ता निकाला है, और निकाल रहे हैं । अंत में मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहती किन्तु गुजरात की हालत क्या है यह इस सदन को देख कर ही पता चलता है । किस किस को उस में कितनी दिलचस्पी है इस को भी आप देख सकते हैं। गुजरात को एक राजनीतिक प्लेटफार्म बनाने के अलावा गुजरात के विकास के लिये, उस के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिये किसी को उस में दिलचस्पी नहीं है । इसलिये मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि गुजरात के लोगों को अभी इस हालत में सिर्फ पानी चाहिए और अनाज चाहिए । गुजरात की जनता को चुनाव की कोई जरूरत नहीं है । धन्यवाद ।

श्री भैरों सिंह शेखावत (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उस समय इसी सदन में एक आपत्ति उठाई गयी थी कि जब तक गुजरात की विधान सभा का चुनाव नहीं होगा उस समय तक राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। सरकार की ओर से इस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय का मत जानने के लिए प्रेषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की ओर से जो दावा प्रस्तुत किया गया या सरकार का जिस प्रकार का दावा था उसके अनुसार सरकार चुनाव केवल इसलिए नहीं कराना चाहती थी कि समय तक गुजरात के डिलिमिटेशन का कार्य संपूर्ण नहीं हो सका था। सरकार ने उस समय बार-बार यह कहा कि यदि कांस्टीट्यूएंसी के डिलिमिटेशन का कार्य पूरा हो जाए तो सरकार को चुनाव कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी और इसी आधार पर मुख्य रूप से इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकार किया कि डिलिमिटेशन के अभाव में चुनाव कराना किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है ।

डिलिमिटेशन का कार्य पूरा हो चुका, इलैक्टोरल रोल्स फाइनल पब्लिश हो चुके, उसके बाद कोई बहाना नहीं था कि गुजरात म चुनाव सम्पन्न नहीं कराये जा सकते । यह नया कारण ढूंढकर लाया गया है कि गुजरात में अकाल है और अकाल पीड़ित क्षेत्रों में चुनाव नहीं कराये जा सकते ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि देश के बहुत से हिस्से हैं जिनमें लगातार अकाल की स्थिति बनी रहती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यू०पी०, उड़ीसा, बिहार, आंध्र और तमिल नाडु के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें किसी न किसी भाग में हर वर्ष अकाल की स्थिति रहती है । जिस समय हमारे देश के नेताओं ने संविधान का निर्माण किया उस समय वे इस परिस्थिति से परिचित न हों, की इस प्रकार की स्थिति नहीं है । उन्हें भी इस प्रकार का ध्यान था कि देश में अकाल, बाढ़ आदि ऐसी स्थितियां आती हैं लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया कि इस प्रकार की स्थितियों में चुनाव नहीं कराये जा सकते ।यह भी नहीं है कि 1952 से लेकर 1972 तक कभी ऐसी स्थितियों में चुनाव नहीं कराये गये । राजस्थान और मध्य प्रदेश ये दो राज्य ऐसे हैं जिनके अधिकांश हिस्सों में चुनाव के वक्त पर अकाल था और भारत की सरकार ने वहां चुनाव कराये । तो अब तक इस तर्क के आधार पर चुनाव स्थगित किया जाना, मैं समझता हूं कि लोकतंत्रीय परम्पराओं के विपरीत है और यह सरकार की स्वयं की राजनीति है जिसको बहाना बनाकर चुनाव टाले जा रहे हैं । वहां तो अकाल पड़ा ही है, स्वयं कांग्रेस पार्टी में भी अकाल पड़ा हुआ है, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं । जो उम्मीदवार हैं वह चुनाव लड़ने का साहस नहीं करते । चुनाव होगा तो पता लगेगा (*Interruption*) चुनाव होगा तो उस दिन पता लगेगा कि गुजरात में कितने कांग्रेस के लोग निर्वाचित होकर आ रहे हैं । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य एक बात तो जानते होंगे कि गुजरात में आज कांग्रेस की तरफ से आम सभायें नहीं होती हैं । वे इतने शर्मिन्दा हैं कि जनता के समक्ष खड़ा होने में उन्हें शर्म आती है । अहमदाबाद में बरुवा साहब ने जहां मीटिंग की वह स्थान मैं देखकर आया हूं कि कितनी पुलिस प्रोटक्शन में एक छोटे से स्थान पर ले जाकर बरुआ साहब को आपने खड़ा किया । उस स्थान की अहमदाबाद से तुलना की जाये तो कहा जाएगा कि कांग्रे अहमदाबाद से सिकुड़ कर एक गली में आ गई । तो अकाल है तो कांग्रेस पार्टी में है । उसके कारण ही आज उनको साहस नहीं हो रहा है वहां पर चुनाव कराने का मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर वहां पर निर्वाचित सरकार होती तो वह अकाल की व्यवस्था नहीं कर सकती थी ? और कांग्रेस पार्टी के लोग यह समझते हैं कि निर्वाचित सरकार होती तो अकाल की व्यवस्था नहीं कर सकती, केवल ऐडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है, तो मैं निवदन करूंगा कि वह अपनी आलोचना स्वयं कर रहे हैं वह लोकतान्त्रिक व्यवस्था के ऊपर अपनी अश्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। वहां के अकाल के बारे में अभी एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 13 हजार गांवों में अकाल पड़ा हुआ है। उपसभापति महोदय, यह बात सही है कि उनको 80 ग्राम अनाज मिलता है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस टास्क बैसिस पर पर उनसे काम लिया जा रहा है उनमें से किसी भी मजदूर को 3 रुपये रोज से अधिक मजदूरी नहीं मिल पाती । गुजरात के आंकड़े उठाकर देखें कि गुजरात में कितने प्रतिशत ऐसे मजदूर हैं जिनको 3 रु० रोज के हिसाब से मिलते हैं और काम का मापदण्ड 21 दिन से होता है, कभी 28 दिन से होता है और जब काम का मापदण्ड हो उस दिन उसको कितने रुपये मिलने चाहियें, यह निश्चित किया जाना चाहिये । सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्सन जरूर हैं कि जल्दी से जल्दी पेमेंट किया जाये, लेकिन उनको पमेंट नहीं किया जाता है । इस वास्तविकता को छुपाया नहीं जा सकता । यही कारण है कि— आप सुनकर ताज्जुब करेंगे—गुजरात में लोगों की भूख के कारण ऐसी स्थिति बन गई कि गुजरात के जामनगर, भड़ोंच, कैर, सुरेन्द्रनगर, कच्छ, राजकोट और सावरकांटा आदि क्षेत्रों के अन्दर नाइट ब्लाइंडनेस का प्रसार भयंकर रूप से हो रहा है ।

आज गुजरात का असैसमेंट आप करा लें तो आप पायेंगे कि 50 हजार आदमी इस बीमारी से मरे हैं । यह बात मैं नहीं कहता । सरकार ने स्वयं एक टीम भेजी है उसने यह स्वीकार किया है कि विटामिन 'ए' की डैफिशिएंसी के कारण सारी समस्यायें पैदा हो रही हैं । सरकार ने पूछा कि इसका इलाज क्या है ।

"The most important measure for combating this disease is to ensure adequate

[श्री भैरों सिंह शेखावत]

availability and intake of food rich in Vitamin A. As a sort of a measure, the problem can be remedied by the administration by ensuring supply of large doses of Vitamin A periodically."

अब मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी करना चाहूंगा कि क्या वहां नाईट ब्लाइन्डनैस की बीमारी नहीं है ? क्या वहां विटामिन 'ए' की कमी नहीं है ? क्या वहां के लोग न्युट्रिशिव डाइट न मिलने के कारण बीमार नहीं हो रहे हैं ? क्या इन सब की कमी के कारण लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है ? यह सब कुछ हो रहा है । इसका इलाज नहीं होगा तो इसका अर्थ यह होगा अगर आप चुनाव करा लें तो निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधि, विधायक के अन्दर से यह आवाज उठेगी और वे दुनियां में जाकर कहेंगे कि अमुक क्षेत्र में न्युट्रिशिव डाइट नहीं मिल रही है । जानवर भूख से मर रहे हैं । आज हालत यह है कि गुजरात में कोई कहने वाला नहीं है । अगर सरकारी अफसर यह कह दें न्युट्रिशिव डाइट के न मिलने के कारण नाइट ब्लाइन्डनैस से लोग मरे हैं तो उसके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाएगा तो वह भी लिखित रूप में इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । मैं दावे के साथ कहता हूं कि गुजरात के अन्दर 6 लाख पशुओं में से 1 लाख पशु आज अपने प्राण छोड़ चुके हैं क्योंकि सरकार ने कोई चारे की व्यवस्था उनके लिये नहीं की थी । चारे की व्यवस्था न होने के कारण जिन लोगों के पास कैटल पापुलेशन है, जिनके पास यह सबसे बड़ा धन है गुजरात के अन्दर आज वह धन समाप्त हो गया है ।

मैं उपसभाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि यदि चुनी हुई सरकार होती तो ऐसा न हुआ होता । आज न वहां पंचायतें हैं, न म्युनिसिपल्टीज के चुनाव हो रहे हैं और न वहां कारपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं । चुनाव पद्धति को बिलकुल ताक पर रख दिया गया है । इसके कारण आज लोगों की आवाज सरकार के पास ले जाने के लिये कोई साधन नहीं रहा और कोई साधन न होने के कारण लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं दूसरे प्रश्नों को भी इस सदन में रखना चाहूंगा । हिन्दुस्तान की सरकार ने अकाल के कारण को लेकर एडवांस प्लान असिस्टैन्स के रूप में गुजरात को 4 करोड़ रुपये दिये हैं । यह एक ऐसी मिसाल है जिस पर सदन को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए । सिक्स्थ फाइनैंस कमीशन के अनुसार इस प्रकार की नेचूरल कलैमिटी के लिये भारत सरकार की तरफ से सहायता दी जा सकती है । आप यह जानते हैं कि गुजरात के अंदर अकाल की स्थिति है और गुजरात के पास जितने रिसोर्सेज हैं उनके अकाल की स्थिति का मुकाबला नहीं हो सकता । दूसरी तरफ जो एडमिनिट्रेस्टर है जिनको यह काम करना है उनको प्लान असिस्टेंस के नाम से पैसा दिया जा रहा है । इसका परिणाम क्या निकलेगा ? जो निर्वाचित सरकार आएगी उसको जो प्लान असिस्टैंस मिलने वाली है उसमें से यह असिस्टैंस काट दी जाएगी । मैं समझता हूं यह तरीका ठीक नहीं है कि प्लान असिस्टैंस करें । जो असिस्टैंस का प्रारूप आपने बना लिया है और जो विकास का काम आप अपने हाथों में लेना चाहते हैं वह पूरे नहीं होंगे । मैं समझता हूं भारत सरकार को सिक्स्थ फाइनैंस कमीशन की रैकमन्डेशन के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए वरन जो भी बैकवर्ड स्टेटस हैं उनमें जो विकास होने हैं वह स्वतः रुकेंगे ।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा । आज गुजरात में जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति में एक समस्या शरणार्थियों की है और दूसरी समस्या कर्जे की है । गुजरात में गरीबी भी है । गुजरात के अधिकांश लोग और खासकर अकाल पीड़ित लोग कर्जदार हैं । कर्जे का कारण एक है । आज गुजरात में जाकर कोई देखे तो मालूम होगा कि लोगों ने अपने पशु बेच दिए हैं, लोगों ने अपने बर्तन बेच दिए हैं । लोगों के पास जो जेवर था और दूसरा जो सामान था वह सब उन्होंने बेच दिया और बेचने के बाद उनको जो आइडैन्टिटी कार्ड मिले होते हैं रोजगार के लिये वे गिरवी रख दिए हैं । इसके एवज में वे बोरोअर्स से सामान लेकर आते हैं जो सामान उनको मिलता है उस पर वे सूद लेते हैं । इस प्रकार से जो कुछ उनको मिलता है वह बोरोअर्स खा जाते हैं । तमाम राज्यों में जो मनीलैंडर्स हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया गया । कई राज्यों में जहां पर जनतंत्री व्यवस्था है, मनीलैंडर्स को गिरफ्तार तक किया गया है । यू० पी० में और कुछ अन्य राज्यों के अन्दर जो लोग गरीब थे, जिन्होंने कर्ज ले रखा था और जिसका इंटरैस्ट बढ़ता जा रहा था, उसके सम्बन्ध में आर्डिनेन्स निकाले गये हैं । मैं समझता हूं कि अगर गुजरात के अन्दर भी चुनी हुई सरकार होती

तो गरीब लोगों को मनीलैंडर्स के चंगुल से छुड़ाने के लिए कोई आर्डिनेन्स अवश्य इशू किया जाता। लेकिन अभी तक वहां पर इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि सारे हिन्दुस्तान में पिछले तीन महीनों में एक अभियान चलाया गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन बांटी जाए। हम सब जानते हैं कि गुजरात के अन्दर 18 लाख 21 हजार एकड़ जमीन ऐसी है जो लोगों में बांटी जा सकती है। लेकिन आज स्थिति वहां पर यह है कि उस जमीन के ऊपर प्रभावशाली लोग एनक्रोचमेन्ट करते जा रहे हैं और शासन की तरफ से इस एनक्रोचमेन्ट को रेगुलराइज भी किया जा रहा है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन बांटने के संबंध में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या की तरफ शीघ्र ध्यान दिया जाए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गुजरात एक सीमावर्ती प्रदेश है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि पाकिस्तान युद्ध की तैयारियां कर रहा है। राजस्थान और गुजरात बोर्डर एरियाज पर स्थित हैं। आप इस बात को स्वीकार करें या न करें, पाकिस्तान पूरे युद्ध की तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में जितने भी हिन्दू थे उस सारी हिन्दु पोपुलेशन को वहां से हटकर पीछे माइग्रेट कर दिया गया है। उन लोगों की जितनी भी सम्पत्ति थी वह सब छीन ली गई है। सन् 1971 के युद्ध के बाद और युद्ध के समय पाकिस्तान की जो जनता हिन्दुस्तान में आ गई थी, हिन्दुस्तान की सरकार की अकर्मण्यता के कारण वापस जाना पड़ा और पाकिस्तान की सरकार ने उनको कंसंट्रेशन केम्प्स में भेज दिया है। पाकिस्तान ने अपने इस क्षेत्र में फौजें लगा रखी हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार अपनी सरहदों के ऊपर फौजी तैयारियां करे या न करे, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जनता रहती है उन के अन्दर इस प्रकार का आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है जिससे वे किसी भी स्थिति का मुकाबला कर सकें। मुझे मालूम है कि सन् 1971 में कुछ शरणार्थी हिन्दुस्तान में आये। उनमें से कुछ गुजरात में रहे और लगभग छः हजार गुजरात में बस गये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दुस्तान में आये उन के पास पैसा कम नहीं था। उनके पास जानवर थे, धन था, दौलत थी, लेकिन आज वे गरीबी की हालत में हैं। हिन्दुस्तान की सरकार ने इन शरणार्थियों पर 6 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन उनको गरीब बना कर रख दिया। आज ये लोग सब बेकार पड़े हुए हैं। उनके लिये रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। वे लोग भूमि चाहते थे, लेकिन उनको भूमि नहीं दी गई। वे लोग सुरक्षा के लिये हथियारों का लायसेंस चाहते थे, वह भी उनको नहीं दिया गया। हमारा यह दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने हमारे साथ युद्ध में साथ दिया उनकी हम कोई मदद नहीं कर पाये। इसके विपरीत पाकिस्तान के सैनिकों के लिये हिन्दुस्तान की सरकार ने 35 करोड़ रुपये खर्च किये। उनको जेलखानों में रख कर तनख्वाहें दीं और जिन लोगों ने भारत के लिये अपना सर्वस्व कुरबान किया उन के लिये हम कुछ नहीं कर पाये। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने इलाके में पूरी सैनिक तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों के लोग आज कह रहे हैं कि अब की बार अगर युद्ध हुआ तो गुजरात और राजस्थान की सीमा से होगा। हम उस सीमा के अन्दर जितना ज्यादा घुस सकते हैं उतना घुसेंगे। इसलिए मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम सन् 1971 के युद्ध में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया था, आज हम उन के साथ इस प्रकार का व्यवहार करें कि वे लोग अपने को सुरक्षित अनुभव कर सकें। सीमावर्ती क्षेत्रों में आज इस प्रकार का विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान ने अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी पैदा की तो वे लोग भारत आ सकें। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस बात को राजनीति से इतना जोड़ने की कोशिश की गई है कि यदि उन लोगों को हमने किसी प्रकार से यहां पर शरण दी तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप यह मान कर भी चलें कि आप उन को गोली से मार दें तो वे स्वीकार कर लेंगे

[श्री भैरोंसिंह शेखावत]

लेकिन पाकिस्तान में जाने वाले नहीं हैं। आप, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद, जो रिहैबिलिटेशन के नाम पर किया, यदि उनको ही करोड़ रुपये दे देते तो उन सबका रिहैबिलिटेशन हो जाता। इस आधार पर मैं कहना चाहूंगा सरकार उनके प्रश्न के ऊपर जितनी जल्दी हो गम्भीरता से विचार करे, ऐसी स्थिति न हो कि पाकिस्तान से आपको युद्ध करना पड़े और उस समय उनका इंटरैस्ट हल करनेके बारे में आप किसी प्रकार की चिन्ता प्रकट करें।

अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर अकेले यह एक बाढ़ की समस्या ऐसी समया नहीं है कि जिसके कारण चुनाव नहीं कराए जा सकते। गुजरात में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिस समय आंदोलन चला उस समय भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के नारे लगाए गए और आज भ्रष्टाचार की रोकथाम क्यों नहीं हो रही है। यदि लोकायुक्त की नियुक्ति हेतु कानून बन जाएं और कानून के आधार पर जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के काम किए हैं उनका प्रोसीक्यूशन होता तो वह संभव था। आज भी सरकार लोकायुक्त के संबंध में मौन है, भारत सरकार दिल्ली में मौन है, गुजरात शासन गुजरात में मौन है। लोकायुक्त का कानून बनता तो जनता के सामने अवसर आता उन सारे भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को कठघरे में लाकर खड़ा करते।

अंत में लेबर के संबंध में कहना चाहूंगा। भारत सरकार ने कुछ नियम बनाये हैं लेबर वेजेज के बारे में। उसके अनुसार यह है कि फलां फलां इन्डस्ट्रीज के ऊपर वैं लेबर वेजेज के कानून लागू होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से गुजरात में अभी तक ऐसा कानन है जो कानून कुछ इंडस्ट्रीज पर नहीं लगाया है, जैसे मैं निवेदन करना चाहूंगा —

Rice, Flour and Dal Mills, Road construction or Building operations, Cotton Ginning and Cotton Pressing manufactory, Printing Presses, Shops and . . .

इस प्रकार की कई संस्थाएं हैं जिनके ऊपर मिनिमम वेजेज का कानन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगा पाया। इसलिए मरी मांग है कि कम से कम औरों का हित करने के साथ-साथ उन गरीबों का हित किया जाए जो वहां काम पर लगे हुए हैं ताकि उनके ऊपर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू हो जाए।

एक बात कहकर मैं भाषण समाप्त करता हूं। हिन्दुस्तान का एक-तिहाई काटन गुजरात के अन्दर पैदा होता है लेकिन दुर्भाग्य से इस बार काटन कारपोरेशन ने 1700 बेल्स गुजरात के अंदर खरीदा है। एक-तिहाई काटन हिन्दुस्तान का गुजरात में पैदा हो रहा है लेकिन सरकार इस एक-तिहाई काटन को खरीदने को तैयार नहीं है और उनका एक्सप्लाईटेशन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, एक तरफ अकाल है, एक तरफ काटन की पैदावार बड़ी है, तो सरकार, जो कुछ भी पूंजी काटन कारपोरेशन को मिल रही है उसके आधार पर गुजरात के किसानों का कपास ज्यादा से ज्यादा खरीदें इस बात का प्रबंध करे।

SHRIMATI SUMITRA G. KULKARNI (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, wild some effort, 1 have gone through the budget proposals for Gujarat for 1975-76 and the two Appropriation Rills which are for the consideration of this House. Sir, 1 would say that it is by and large a very good budget as can be expected from a bureaucratic administration working under President's rule. With their limited imagination, they have come up with whatever they could suggest. But I would still like to submit to you that this Appropriation Bill and these budget proposals should not be viewed as they are, but they should be viewed in the present context of Gujarat. Otherwise, 1 would say that the House should pass these- budgetary proposals because by and huge they are satisfactory. But when viewed against the present context of Gujarat, there are a number of issues which come up before this House. Before 1 put forward any point, f will just inflict a few statistical figures on this House. Sir, time and again it has been submitted here that Gujarat is passing through a serious drought situation. As everybody knows, out of 18,100 villages, rriore than 12.000 villages have been declared as scarcity villages. Our population in Gujarat is 2.75 crores. We

may take that one crore is the urban population. Out of the remaining 1.75 crores, a little less than half is the adult population which requires employment in the rural areas. As against this, you can see that today there are only 7 lakhs of persons who are getting relief under scarcity work programmes. Seven lakhs out of 75 lakhs have got relief. That works out to be less than 10 per cent. This is the real crux of the matter. Only 10 per cent of the population which requires help at this time is getting help. They are getting help under the scarcity schemes while the rest of the 90 per cent is not being attended to and thus causing trouble in the entire rural areas and the drought-stricken area of Gujarat. Now, Sir, what are the scarcity relief works that are usually taken up ? They are : minor irrigation, soil conservation, area development, agriculture and afforestation. These are the essentia! things which should be taken up. In this Appropriation Bill, the amount that is being allocated for this is Rs. 4.75 crores and for afforestation Rs. 8,45,000/-. Sir, it is Rs. 8,45,000/- for afforestation when one-third of the coast of the country is in Gujarat, and it is Rs. 4 crores for minor irrigation, particularly in 3Ught area. Sir, this shows how this Appropriation Bill is inappropriate in the present conditions of Gujarat.

Sir, the second point which 1 would like to make is that so far, till the end of the last month, we have spent Rs. 33 crores on relief work in Gujarat. In the next year, according to these Budget proposals, it works out to another Rs. 32 crores which is under the various plan projects and non-plan projects. And under the DPR programme, we have got another Rs. 32 crores. The total amount available for expenditure for fighting this scarcity is Rs. 66 crores. Sir, I would like to submit that in the year 1972, Gujarat had a very serious drought and at that time there was a popular Government. In those days Rs. 81 crores were spent on the scarcity relief work in Gujarat. Sir, since then, the price index has gone up and everything is costing much more. So, it will be logical if I suggest that we require, if not double the amount of Rs. 81 crores, at least, Rs. 150 crores. As against that, according to these budgetary proposals, only Rs. 66 crores are available now. Now, I would like to ask this august House as to exactly what kind of relief work can we do with mere 66 crores of rupees. Sir, then it was Rs. 81 crores. Now, it is Rs. 66 crores. Instead of increasing it to Rs. 100 crores or Rs. 120 crores, they are making it lesser and lesser. This[1] is what is troubling the people of Gujarat. And we the Members, who are coming from Gujarat, who have to counteract our constituents, have to explain them as to what is happening. And this is where the whole rub lies.

Again, Sir, the drought in 1972 had come soon after the 1970-71 bumper crops. In those days, people had some savings and they were in a better position to fight the drought condition, but now, after three years of consecutive calamities, one after the other, the drought conditions are prevailing in Gujarat, and in £aitch it is nearly for the last four or five years. Sir, all the saving with the people has been wiped out. People are suffering from diseases, malnutrition, and many people are suffering from night blindness. Against those ravages of drought conditions, we have to give them relief. Are we giving sufficient relief in the face of these difficulties ? And this is the basic question which I would like to pose *vis-a-vis* this Appropriation Bill and the budgetary proposals. Sir, relief is needed today. Maybe, provisions are made for next year and they will come. But God willing, we will have rains in our part by 15th of June. By 30th June, most of the labourers and people will be going and working in their own fields. Relief works will not be needed at that time. Whatever relief is needed, is needed now and today. What is the use of allocating for a later period ? We have to spend nearly Rs. 100 crores, if not Rs. 100 crores, at least Rs. 70 to Rs. 80 crores from now on till 30th June. Are we in a position to do this thing ? I don't find that preparation anywhere. There is no evidence that the Government or the Administration that is going on there has got the preparedness for fighting the scarcity on this

[Shrimati Sumitra G. Kulkarnl]

vast scale. Out of these Rs. 33 crores which we have got, Rs. 15 crores have been taken out for the Plan projects. The Plan projects are meant for the improvement of our backward areas. If we use that amount today for attending to the scarcity relief work, which is essentially not of a lasting kind of work. Sir, next year, when we will require this money for the development of backward areas, we will not have the noney. Therefore, the result will be that the backward area will become more backward because adequate funds are not available to it and also because we are attempting to take loans against the plan projects of next year. Now. this is a very faulty policy and it is a very defective thing. It may appear that today we have provided for Rs. 15 crores but that is not going to be because that is being taken away from something which was due tomorrow. Apart from that, this money is the right of backward areas and it cannot be spent on ^car-city relief works. Now, Sir, against this background, my submission is that this Appropriation Bill is falling short of what it should have been and what it could have done. That is why I say that though the Appropriation Bill, on the face of it, reads quite satisfactory but in actual working it falls short of all expectations and is going to hurt the people of these parts tremendously.

Now, Sir, these budgetary proposals, which have been put up. are making the rich richer and poor poorer. 1 will illustrate how it is so. In the name of incentives, the industrialists are getting large amounts but others are not getting any such attention though they want it. Now. industrialists are having enough capital of their own and they do not require any incentives but under these budgetary proposals incentives are being offered to them. Now, I will give you a specific instance. Gujarat is famous tor its textile industry. In the textile industry in the last two years we have had a record profit. Never before in the history of 120 years of the textile industry, has the industry earned this amount of profit. But, today, when the Government wants and the poor people of India are in need of standard coarse cloth, the textile industry of Gujarat has refused to produce standard cloth. There are, of course, penalties but the Government of India does not seem to be able to enforce the discipline on these recalcitrant textile industrialists. They are not producing standard cloth. They have made huge profits which they are not willing to share with the people of Gujarat and they are also not willing to come to the rescue of the people of Gujarat by producing standard cloth. Of course, the Government will say that penalties are imposed ; but that penalty is just a mockery, it is not a proper penalty at all. It is merely an apology for penalty and it is much easier and cheaper to pay the penalty and be done with it. That is what the textile industry is doing. On the other hand, Sir, the price of standard cloth has been raised doubly. So, it will be seen tliat on the one hand the prices of standard cloth have gone up and, on the other hand, the textile industrialists are not producing the standard cloth and the result is that pooi people are getting more and more frustrated and in greater difficulties.

Sir, another thing that I want to point out is that the Gujarat Budget has ceme up with a deficit of Rs. 3.27 crores. Now, from where are we going to meet this deficit: again by indirect taxes, which, in turn, is again going to affect the people at large, i.e., the poor people, who constitute the majority of the people. That shows that the burden falls again on the poor people of Gujarat. That is why I say that the Appropriation Bill and the budgetary proposals have to take a more realistic attitude and take into consideration how these proposals are going to react and influence the functioning of the people and their welfare.

In this background, Sir, I want to make four recommendations. Hon. FinanVe Minister is not here but the Home Minister is sitting and I would claim his attention on these issues.

Firstly, Sir, Gujarat is very rich in **its** oil resources. We have been producing crude for the country and we are very proud of it. Although the crude prices have gone up in the course of the last year and a half, our royalty has not been increased. Today we are getting Rs. 15 per metric tonne of crude that we produce. As against this, the prices have gone up by 400 to 500 per cent. But we, the people of Gujrat, are not getting any share out cf this royalty which is our right. If only we were to get the royalty that we are c|aiin ing, *i.e., as* against Rs. 15 per metric tonne if we are to get Rs. 500 per metric tonne of crude, we would not come to the Central Government for any assistance for anything, may be drought or anything else, because then there would be sufficient money. This is a very legitimate demand of the people of Gujarat, namely, 2 P.M. the royalty on crude should be again refixed in the light of the oil bonanza that the oil industry is enjoying. Why should not a portion of that bonanza be given to the people of Gujarat also?

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra): Gujarat will be like Abu Dhabi!

SHRIMATI SUMITRA G. KULKARNI : Sir, my submission through you would be that the reference of the Gujarat Government under President's rule is lying with the Petroleum Minister and the Petroleum Minister should expedite this reference and take a decision at the earliest so that Gujarat gets its rightful dues.

Sir, the second point that I have got is, the 6th Finance Commission's recommendation was that relief to the extent of Rs. 4-1/2 crores should be given. But that was envisaged for normal times and not abnormal times. It was expected that the State Governments will be able to attend to their normal periodical drought conditions. *{Time bell rings)* Sir, I need only five more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Not five but two minutes.

SHRIMATI SUMITRA G. KULKARNI: I will be finishing quickly.

We have been caught up very much before. Hardly the recommendations had come the drought also came. The Gujarat Government had no time to build up its surplus stock so as to meet the drought conditions. So, if the recommendations are forced on us today we will be in a real difficulty. Even Mr. Brahmananda Reddy who was the Chairman of the 6th Finance Commission, has submitted on the floor of this House that this recommendation should be withdrawn. So I would like to urge upon the Finance Minister that he should rise to the occasion and cut through the inertia that his Ministry is suffering from and they should take a bold decision that the 6th Finance Commission's recommendations should be postponed.

Now, Sir, the third recommendation of mine is, through you I would like to submit, if we want to fight scarcity and give-some relief to the people of Gujarat, then the honourable Railway Minister should come forward. We have got the Bhavnagai -Tarapur railway line which has been fully approved but the scheme is lying here and gathering dust in the shelves of the Railway Board. Sir, my submission is that if we just start work on- this line, it will give tremendous relief to the people of Gujarat by way of providing work to many people and encouragement to some people because some people can thus be taken care of. Unless this railway line of Bhavnagar-Taiapur is taken up, no large-scale work or help can be given to them. Similarly, Sir, broad-gauging work of the Viramgaon-Okha line also should be expedited so that it can take five to six thousand labourers instead of the present three thousand labourers who are employed there today. If that kind of relief comes, it will help Gujarat.

Sir. the last point is about the glut in cotton. Gujarat is the only part of the country where we are producing *not* only one-third of the entire cotton produced in the country but also long-staple cotton

[Shrimati Sumitra G. Kulkarni]

which matches itself with the Egyptian cotton. We had to invest a hell of a lot on research and also on capital to produce this. But today, unfortunately, the Cotton Corporation is not lifting this thing with the result that our godowns are glutted with long-staple cotton and it is being sold along side short-staple cotton. This is a financial loss to the agriculturists of Gujarat who are already suffering and this should be avoided because this long-staple cotton, if lifted, is not going to cause any loss to the Government. We can export it and earn foreign exchange and that way the Central Government can benefit itself and also the agriculturists of Gujarat.

Now I want to reply to Mr. Shekhawat because he has mentioned. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) : The Minister will reply him. Already you have taken...

SHRIMATI SUMITRA G. KULKARNI: He has said that today our party position is different. Sir, we are quite capable of taking care of ourselves and we will meet any situation that will arise.

The second thing he said is. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Now you need not reply to all his points.

SHRIMATI SUMITRA G. KULKARNI : He said that the people of Gujarat should be prepared for facing an attack from Pakistan. Let me tell him. Sir, drought or no drought the people of Gujarat are ever vigilant and ever ready to fight any kind of attack from Pakistan or any other country. We do not require anything. We have been vigilant not today but through the centuries. No other party should feel that because the people of Gujarat are not prepared they should be given encouragement. The people of Gujarat are fully aware of the danger that they are facing and they are quite capable of facing that danger. I would only submit to the Opposition that they need not have anxiety on the score that the people of Gujarat are not ready. We are contributing in the national defence as they are doing through the centuries.

Thank you.

SHRI UMASHANKAR JOSHI: Sir, I won't take long. The main calamity in Gujarat is that of drought. In our language we say that there are two types of difficulties—*aasmani* and *sultani.* The *aasmanl,* the heavenly wrath has descended on Gujarat for the last three years and last year the wrath of the Government descended relentlessly on the people of Gujarat and it is not in any mood to end itself. The elections have been postponed on account of the capricious reason of there being drought conditions. I reminded the Home Minister at the Legislative Consultative meeting when he also referred to the law and order situation in Gujarat, that they were keeping their options open while they were denying the people of Gujarat their democratic right to have elections and through elections a popular government. Meanwhile, momentous decisions are being taken and the people of Gujarat are deluded into believing that the Narbada water dispute is being tackled by the Government and tackled in a way that is beneficial to the people of Gujarat. I do not want to speak as one mainly interested in Gujarat affairs because very rightly in the agreement that was signed it is mentioned: It is agreed that the development of the Narbada waters should no longer be delayed in the best national interest. This is a matter of national interest. Where questions of security are concerned we say that we will have only bilateral discussions, we will solve our disputes by holding bilateral discussions and this is a very sound policy but where inter-State matters are concerned why is it not possible to solve these matters ?

The four projects that have been granted in favour of Gujarat and the other four that have been in favour of Madhya Pradesh do not take us far, as far as the main dispute is concerned, let us avoid

the word 'dispute', as far as the main solution is concerned. We want production of more foodstuffs. It will take 10 or more years even after you decide upon the height of the Navagaon Dam. As far as Gujarat projects which have been cleai-ed are concerned nothing special has been done to Gujarat. As far as Madhya Pradesh projects are concerned they can be prejudicial to the final decision to be taken on the height of Navagaon Dam. So I would urge upon the Government, specially the Minister tor Agriculture who has a dynamism about him and who has a way of tackling whatever difficult problems he has faced in any Department in his charge, to consider these problems seriously. He said the other clay in Ahmedabad that if we could solve such problems as the river water disputes, not only we could be self-sufficient in the matter of foodgrains but we could even export foodgrains. I would like to agree with what he says, but precious little is done in this matter. The people of Gujarat are just deluded into believing that they are really getting something from these Narmada water projects. Sir, the Government should see to it that the main pro- j ject is cleared as early as possible. This would fortify us against the heavenly ' wrath that descends upon the people of that part of our country.

Why should elections be not held ? No cogent reason is advanced. The Minister said in the other House that the present time is not congenial to the holding of elections. Congenial to whom ? To the ruling party. My friend Shri Tndradeepji suggested that the ruling party has its own designs in the matter. Why could they not announce at the Consultative Committee meeting two months ago that they would not hold the elections before the rains came, *i.e.,* beore the monsoon ended ? Why could they not give—or did not I give—even last month a categorical reply in this matter by stating that the elections j would be held in a certain month ? The Government is playing with the fate of the people of Gujarat, and their credibility.

as it stands today, does not permit the people of Gujarat to think that they are serious in the matter. There is a doubt lurking in the minds of the people that elections may not be held even after the monsoon. An atmosphere of fear psychosis is sought to be created in this country in certain ways. This may land us into a political situation where elections may be a thing of the bygone times. So let the Government listen to the legitimate demand of the people of Gujarat. They have been agitating for the past few days, and they are bound to agitate, for early elections in Gujarat, in the absence of the popular Government, what do you expect? Governor's Rule for the people? At the last Budget discussion, I drew the attention, of the hon'ble Minister that during the previous President's Rule, the available cultivable land in Gujarat was distributed among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people—a portion was distributed. Could they not proceed with this activity ? I would like to hear that they have distributed all available land to the landless, specially those among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Despite the slogan mongering in favour of socialism, very little is done for landless among the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes all over India, specially so in Gujarat which is under the President's rule. The Budget for the country as well as what is under discussion today are the documents which show that even a non-socialistic Government could not have come forward with more reactionary proposals than are touched in these documents. Thank you. Sir.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, हमारे लिए आज गुजरात के अन्दर जो मैन क्लेमिटी है वह प्रेजीडेन्ट रूल है। मैं समझता हूं कि अगर राष्ट्रपति शासन वहां पर न हो और वहां की जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में शासन हो तो बहुत-सी बातों की हम लोगों को जानकारी हो सकती है। अक्सर कहा जाता है कि वहां पर सूखे की स्थिति है। इंदिरा जी इस समय यहां पर नहीं हैं। वह कहती हैं कि मैं गांधी जी के रास्ते पर

[श्री राजनारायण]

चल रही हूं। गांधी जी का एक वक्तव्य सन् 1946 का है। जो सरकार बाढ़ और सूखे को दैवी प्रकोप मान करके जनता की रक्षा नहीं करती और सारा दोष दैव पर मढ़ देती है वह सरकार पापी और पाजी, दोनों है। गांधी जी के शब्दों को अगर देखा जाय तो राष्ट्रपति शासन वहां पर पाप कर रहा है और दुष्टता भी कर रहा है। यहां पर माननीय मंत्री महोदया बैठी हैं। 23 करोड़ रुपये राष्ट्रपति शासन के दौरान जनता से वसूल किये गये हैं नये टैक्सों के रूप में। बिना पार्लियामेंट को विश्वास में लिये यह काम किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में 23 करोड़ रुपये कैसे वसूल किये गये और क्यों वसूल किये गये? इसमें पार्लियामेंट की सैंक्शन क्यों नहीं ली गई? इतना जघन्य अपराध यह सरकार आज कर रही है। संविधान के साथ और इस देश की जनता के साथ जघन्य अपराध किया जा रहा है। सरकार ने एक तुगलगी फरमान निकाल दिया कि 23 करोड़ रुपया वसूल करो। सरकारी कर्मचारियों ने 23 करोड़ रुपये वसूल कर दिये। यह सरकार संविधान का बहुत दुरुपयोग कर रही है। ये लोग हमें फासिज्म और डेमोक्रेसी की बात बताते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इनको बता सकता हूं कि डेमोक्रेसी क्या है, जनतंत्र क्या है। कंसल्टेटिव कमेटी में इस बारे में कभी चर्चा नहीं की गई और संसद् में इस बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की गई। 23 करोड़ रुपये तुगलगी फरमान से वसूल कर लिये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन-सा जनतंत्र है? क्या यह हिटलेरिजम का रास्ता है या स्टालिनिजम का रास्ता है। 18 हजार 604 गांवों में से 12 हजार गांवों को स्केयरसीटी एरियाज डिक्लेयर किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि स्केयरसीटी एरियाज घोषित किये जाने के बाद इन 12 हजार गांवों में इस सरकार ने क्या किया है? वहां के गांवों के लोगों को इस सरकार ने क्या सहूलियत दी है। जो रिलीफ वर्क शुरु किया गया है वह 4 हजार 5 सौ गांवों में शुरु किया गया है। जब सन् 1972-73 में वहां पर विपत्ति आई तो रिलीफ के काम पर 94 करोड़ रुपये खर्च किये गये और इसमें 82 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार ने दिये। लेकिन इस बार केवल 37 करोड़ रुपये रखे गये हैं। जबकि 1972-73 की बनिस्बत आज 1975-76 में रिलीफ वर्क की वहां ज्यादा आवश्यकता है। वहां ज्यादा मुसीबत है, ज्यादा महंगाई है, वहां ज्यादा संकट है, और सबसे बड़ा संकट श्रीमन्, वहां आज चारे का संकट है। मुझे गुजरात के बंधुओं ने जो जानकारी कराई है टेलीफोन से, उन्होंने यह बताया कि यहां पर जनता ने तय कर लिया है कि अपने तमाम पशुओं को सरकार के पास ले जा कर के छोड़ेंगे और कह देंगे राज्यपाल से कि अब आप उन पशुओं की रक्षा करो, उनको खिलाओ, हमारे पास चारा नहीं रह गया है जिससे हम उनको खिलाने में समर्थ हो सकें। मैं जानना चाहूंगा, इस स्थिति का सामना करने के लिए गुजरात में यह सरकार क्या करने जा रही है?

और इसी के साथ साथ, यदि जनतंत्र का नाम इस सरकार के मुखारविंद से निकले तो उसे शर्म आनी चाहिए। जनतंत्र एक पद्धति है, जीवन की प्रणाली है सर्वांगीण तानाशाही के विरुद्ध प्रणाली है। जनतंत्र केवल एक मौखिक शब्द नहीं है कि जनतंत्र-जनतंत्र और समाजवाद बोल दिया और समाजवाद आ गया। वहां विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। विद्यार्थियों की पहले मांग यह थी कि जो हमारा खाने का बिल है उसको कम करो, हम खाने का इतना हेव्वी चार्ज नहीं दे सकते, हमारे घर में इतना पैसा नहीं है। और इसी मांग को लेकर के वहां आंदोलन हुआ। सरकार गई, राष्ट्रपति शासन आया, विधान सभा भंग हो गई—आज तक चुनाव क्यों नहीं? कोई भी सरकार अगर अपने को जनतंत्र में आस्था रखने का दम्भ रखती है तो मैं अदब के साथ जानना चाहूंगा कि क्या इस ढंग से वहां का चुनाव टाला जा सकता था? एक बार एक बार, दो बार दो बार, क्या कह कह कर छः महीने के लिए चुनाव टाला गया, क्या कह कर अब छः महीने के लिये और आगे टाला गया? एक सफायी नहीं,

स्पष्टीकरण नहीं। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से, जो वहां पर स्थिति अब पैदा होने वाली है वह बताने जा रहा हूं। संगठन कांग्रेस ने अपना फैसला ले लिया कि हमारा सत्याग्रह शुरू होगा। उनका सत्याग्रह शुरू हो गया है। 250 आदमी कल गिरफ्तार भी हुए थे। इण्डियन एक्सप्रेस के छठे पेज में खबर छपी है :

"Satyagraha for Gujarat poll begins: More than 200 Congress (O) Satyagrahis courted arrest here today some distance from Raj Bhavan, as the party launched its civil disobedience movement for early elections to the Gujarat Assembly"

मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती जी, इसका मुकाबला कैसे करेंगे ? गोली से, लाठी से, लोगों को जेल में बंद करके, लोगों को भूखा मार करके, बेघर-बार करके। एक जेनुइन डिमाण्ड थी कि फिर से चुनाव हों और उस चुनाव को यह सरकार बिल्कुल टालती चली जा रही थी, फिर भी दम भरती है हम जनतंत्री हैं। तो यह खबर है कि 250 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्रीमती जी, याद रखिए, 50 वीमेन भी है। 50 यहां के जैसे नहीं हैं कि दस-दस रुपए पर रिक्शा में बैठा कर इन्दिरा माई की जय कह दिया। वे सत्याग्रह में बिलीव्ह करती हैं, विश्वास करती है। इन्दिरा माई की जय वाली बात नहीं है।

तमाम मार्किट में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, सारे चौक में घूमें। अब विद्यार्थियों ने फैसला कर लिया है कि अब कांग्रेस के एम०पी० को गुजरात में प्रवेश नहीं होने देंगे, अगर चुनाव नहीं होता है तो कांग्रेसी संसद सदस्य गुजरात में प्रवेश नहीं करने पाएंगे...

"The Satyagrahis from Ahmedabad city and Khaira district including about 50 women..."

"... were rounded up after they made a valiant bid to break the concentrated ring of police cordon. They started in a procession through the city from the main market."

एक माननीय सदस्य : यह आपकी डेमोक्रेसी है।

श्री राजनारायण : हमारी डेमोक्रेसी है—क्या भ्रष्ट, क्या निकम्मी, क्या देश की जनता के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे संसदसदस्यों को गुजरात की जनता बर्दाश्त करेगी ? गुजरात में जाकर वे उनकी छातियों में कोंदों नहीं दलेंगे ? (*Interruption*) वे न एम० पीज० को मार रहे हैं और न ही एम०पीज० को कुछ बोल रहे हैं। वे तो केवल यह कह रहे हैं कि हमारे चुनाव करा दो, हमारे चुनाव करवा दो। जनता को विधान द्वारा जो वोट देने का हक है, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता का और जनता के लिए। ये तीन शब्द है। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि मान लीजिये अगर जनता द्वारा चुन भी लिये जावे, अगर सरकार जनता के लिए नहीं है, केवल अपने परिवार के लिए है, तो वह सरकार जनतंत्रीय नहीं है और उस सरकार को डाह देना, गिरा देना, जनतंत्रीय है और जनतंत्र की शोभा इसी में है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : अब आप के दस मिनट समाप्त हो गये हैं।

श्री राजनारायण : अगर हमारे दस मिनट समाप्त हो गये हैं तो हम बैठ जाते है। हम ऐसा उदाहरण यहां पर पेश करना नहीं चाहते हैं ताकि दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करें। इसलिए हम आपकी आज्ञा के मुताबिक अपना भाषण यहां पर ही समाप्त कर देते हैं।

SHRI YOGENDRA MAKWANA (Gujarat): This Budget is a routine Budget. Unfortunately, it is a deficit Budget to the extent of Rs. 3.27 crores as rightly pointed out by Mrs. Kulkarni. The deficit will be collected through indirect taxes and it will be a burden during these scarcity conditions, when the people of Gujarat are passing through critical conditions. The main question before us in Gujarat is the unprecedented drought prevailing there. The Government of Gujarat

[Shri Yogendra Makwana]

has so far spent Rs. 35.50 crores only. The amount for scarcity relief in Gujarat is not large. Last year when there were scarcity conditions Rs. 81 crores were spent by the then popular Ministry. The scarcity condition is rather grave and it will require not less than Rs. 120 to Rs. 125 crores for meeting it.

My esteemed colleague, Mr. Indradeep Sinha, spoke of the Gujarat Vidyapeeth. This noble institution was founded by Bapti with lofty ideals. But what is the condition prevailing there now ? Mr. Morarji Desai who claims himself to be a democrat is no less than a great autocrat and a dictator here. He and his lieutenant, Mr. Ramlal Parikh, who is alleged to be a CIA agent, are crushing the teachers and the student in this Vidyapeeth. Enormous amounts from the University Grants Commission are taken by these people and they are used for their political activities. Mr. Morarji Desai has made his headquarters in this Vidyapeeth, and it has become a centre of his political activities which are carried on from here. Sir, I ask the Government through you whether this money intended for the Vidyapeeth is to be spent for the political activities of Mr. Morarji Desai and of the Congress (O).

Is it for the welfare and for the education of the students of Gujarat who are receiving education in this University ? Sir, since the last 73 days agitation is going on and this autocrat, Mr. Desai, and his lieutenant, as I told you in the beginning, a C.I.A. agent, Mr. Ram Lai Parikh...

SHRI VEERENDRA PATIL (Kar-nataka): On a point of order...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) : Come to the Gujarat Budget.

SHRI VEERENDRA PATIL: I rise on a point of order. It is a well known convention, and also according to the rules, that we should not make wild allegations against 3 nerson who is not in this House to defend himself. If the hon'ble Member wants to say anything against that particular Member he must first inform the Chairman, take his permission andl then he can make the allegation. Mr. Morarji Desai is an honourable Member of the other House. So if there are any allegations, then why not the hon'ble Member persuade his party Members to make this allegation in the other House so that he can give adequate reply or whatever explanation he has to offer he can offer that explanation in the other House. In this House he cannot come and offer explanation. When a pet-son is not in a position to come to this House and offer any explanation with regard to the charges that are being made against him, I think it is not fair on the part of the hon'ble Member to make the allegation.

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : मोरारजी देसाई के बारे में ये कहते हैं कि वे आटोक्रेट हैं।

SHRI VEERENDRA PATIL : He is not a Member of this House. I am not objecting to his making allegations. What I am objecting is that he is a Member of the other House. He can persuade the Members of his party there to make such allegations in the other House so that Mr. Morarji Desai can give a satisfactory explanation.

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : पाटिल जी, ये गुजरात विद्यापीठ के विषय में बोल रहे हैं। इनका कहना है कि उसको केन्द्र से जो, अनुदान मिलता है उसका दुरुपयोग हो रहा है। आपके पास तथ्य हो तो रिबट कर दें।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: My friend is unnecessarily annoyed.

SHRI K. N. DHULAP (Maharashtra)* Ijet him prove the anti-national activities of that particular person. What is the use of making allegations here ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: My friend, Mr. Patil, is unnecessarily annoyed. I have never charged Mr. Morarji Desai

as a C.I.A. agent. I only said that Mr. Ramlal Parikh is alleged to be a C.I.A. agent. Sir, 1 have got many proofs with me. Here, is a leading weekly of Gujarat. I'arivartak, where the activities of Mr. Morarji Desai and Mr. Ramlal Parikh are given in detail. And what is going on in the Vidhyapeeth is also given in detail in this weekly. I do not want to read out every line and page of this weekly.

श्री राजनारायण : कहां का है ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : It is published by your ex-S.S.P. and P.S.P. friends in Gujarat.

श्री राजनारायण : इलैक्शन करादो और उसमें यह सब बोल देना ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA : As I rightly said, this Vidyapeeth has become the headquarters of Mr. Desai and Mr. Ramlal Parikh and is the centre of his political activities. Funds which are allotted by the U.G.C. are diverted and misused for other departments.

Sir, one jeep car and a station wagon is provided for the Rural Extension Services and the department of Social Education to this Vidyapeeth by the U.G.C. which is used for political activities.

Unfortunately in Gujarat nobody is there to point out these facts to the Government and no paper—and when I say no paper, I am taking about the daily papers which are owned by those who are supporting Mr. Morarji Desai —is interested in highlighting these facts. And that is why I am forced to utter these words in this august House and bring it to the notice of the Government. I have already written a letter to the Prime Minister demanding an enquiry into the activities of the management of this Vidyapeeth. Sir, for the Department of Tribal Education and Continuing Education, lot of funds are given to the Vidyapeeth. This Department exists only on paper. There is no such Department at all. And the money taken by way of salaries, etc. is misappropriated. Therefore, I request the Government to institute an enquiry against this Vidyapeeth at an early date.

Sir, so many friends from the Opposition, including Mr. Rajnarain, have talked about elections in Gujarat. I may tell Mr. Rajnarain and his friends that we are never afraid of elections in Gujarat. We are very much for it and we ourselves have demanded elections there. But do you know the condition prevailing at present in Gujarat ? When you talked about scarcity, when you described the pitiable condition of the rural poor in Gujarat, you forgot that this condition in Gujarat is to be handled first and not elections. The people of Gujarat are not interested in elections at present. But they are interested definitely in food. They are interested in meeting this scarcity condition. We are trying our best to meet this scarcity condition and at this time, from the house-tops you shout about elections and divert our attention and the Government's attention. What did Shri Morarji Desai and his party, who always shout about democracy, do during the "Navnirman" movement ? They forced the MLAs to resign. They beat up some of them, as I pointed out during those days in this august House. Even my house was attacked. My family **was attacked.** So **many** others were attacked. Now, these people, the same people who did these things, who killed democracy in fact in Gujarat, are shouting in the name of democracy and asking for elections in the name of democracy. The man who never behaved like a democrat, the man who was ever an autocrat, is now speaking in terms of democracy. What is democracy to him, I do not understand. The ideas of democracy to him are quite different, I think.

श्री राजनारायण : वह एशियन डेमोक्रेसी है ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Why is Mr. Rajnarain so agitated ? Some 13,000 villages out of 18,000 villages in Gujarat are affected and 7 lakh people are employed in these scarcity relief works. There is scarcity of drinking water also in most of the

[Shri Yogendra Makwana]

villages and the whole administration is engaged in meeting this scarcity condition in Gujarat. At that time, how is it proper to hold elections ?

Sir, I say, therefore, that those who are shouting in the name of democracy and those who are shouting for the elections there are not really interested in the elections, but are interested only in achieving their political aims and they have np place in Gujarat. The people of Gujarat have known them rightly during the days of the Nav Nirman Samiti movement. After that also, Sir, they were shouting against corruption. But, Sir, what did they do for removing corruption ? Did they continue their fight against corruption ? I would like to ask my friends who are shouting against corruption and also Mr. Desai and his colleagues as to what they did to remove corruption in Gujarat. What have they done to eradicate corruption from the bureaucracy in Gujarat ? They never did anything about this. They were only interested in killing democracy and in removing the elected representatives of the people of Gujarat and now the"y are shouting for a representative Government there. Sir, I will say that they have no national spirit also. I say this because the Other day, Sir, they wen; to the Raj Bhavan to hoist the people's flag. In the name of the people's flag, they are insulting the national Hag. The national flag is there. What does it indicate ? What is the people's flag ? The national flag also is the people's flag; the tricolour is also the people's flag which is flying on top of the Raj Bhavan in Gujarat. They must realise these things. But they are marching to the Raj Bhavan to hoist what is called the people's flag ! Sir, this is an insult to the national flag. Therefore, those who tire shouting in the name of democracy and in the name of representative government, have no right to talk about these tnings.

SHRI RAJNARAIN : What is your ^cngress party's flag ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : If they are really interested in the welfare of the people of Gujarat, they should go to the villages and they should help the people and try to mobilise money, food-grains and other things from the other parts of the country and bring them to Gujarat to help the people there. But, as I said in the beginning, they are not in terested in the welfare of the people of Gujarat and they are interested only in the welfare of their party. Therefore, Sir, they are .....

SHRI RAJNARAIN : Ours is also trie people's party.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : ... shouting about the elections to be held in Gujarat.

Sir, as I said earlier, the conditions in Gujarat are very difficult and the scarcity there is very acute. Therefore, it is very difficult to collect this deficit of Rs. 3.27 crores from Gujarat and this is a national calamity now there. So, I request the Government to mobilise all the resources for helping the people of Gujarat.

With these words, Sir, I support this.

SHRI VEERENDRA PATII.: Sir, our sympathies go to the people of Gujarat who are, unfortunately, facing an unprecedented drought situation this year.

Sir, I may tell the House that out of the 19 districts there, 14 districts are famine-affected districts and out of the 18,604 villages there, as many as 12,000 villages are badly affected. Sir, this is not the first time that the people of Gujarat are facing such a situation. In the year 1972 also, Sir, there were famine conditions in this State. But this time it is more acute and that is why I say that the famine in that State this year is unprecedented. But, Sir, I must say that the relief measures taken by the Governor are very meagre and inadequate to meet the situation there.

The people are suffering in more than 12,000 villages. But so far the relief operations or works are going on only in 4500 and odd villages. They do not have drinking water facilities. They do not have fodder for their cattle. They are facing unprecedented hardships. And the Governor who is ruling that State at the moment has miserably failed to mitigate the hardships of the people. That's why we demand that only a popular government, if it is installed, will be in a position to face this unprecedented situation successfully. There is an instance or an illustration before us that in 1972 when there was famine, at that time there was a popu-erpment in Gujarat. I think at l ha: time also the ruling Congress was in power. And we are prepared to give credit to the ruling party that during that time in 1972 they did their best to mitigate the hardships of the people. They spent nearly Rs. 94 crores. But what is happening today ? Everybody in this House, whether sitting on that side or on this side—everybody agrees that this time the situation is worse; it is unprecedented. And what is the amount provided for and what is the amount spent ? Hardly 30—33 crores. That's why we feel that because there is no popular government, there are no people's representatives, they do not have any voice. Therefore, the people are suffering. In order to mitigate their suffering, it is very necessary that a popular government should be installed as early as possible.

Sir, the hon. Member on that side says: How can we do this thing when the people are facing unprecedented drought and hardship and where is the time for the bureaucracy to hold elections and all that ? Sn, I must humbly submit that if they wanted to hold elections they would have held the elections in the month of either November, December or January. Nothing had prevented them from holding elections. Now an agitation is going on and in today's papers we read that two hundred and odd people have courted arrest. Sir,... 8RSS/75—4

SHRI YOGENDRA MAKWANA: You know that during December the delimitation work was going on.

SHRI VEERENDRA PATIL: At that time, delimitation work was going on, and now the Election Commission says, "We are prepared to hold elections at any time". The Election Commissioner has coma out with a statement— and it has appeared in all papers— that so far as the Election Commission is concerned, they are ready to hold the election even at a fortnight's notice. Now the delimitation work is complete. But you say that there is now drought. You find out some excuse or the other to postpone elections. Why I am laying emphasis on this is because, I must say with a heavy heart that the ruling party is losing faith in democracy. They are losing faith in democracy, because in Gujarat, they can say, because of the drought they are not in a position to hold the elections, But what is happening in other States ? I can quote the instance of my own State. There is no drought in my own State. Taluk Board elections. Taluk panchayat elections, Panchayat elections, etc. have been put off. Elections to the Bangalore Corporation have been put off. Elections to Municipalities have been put off. I want to know, why ? In Broach, I do not think, conditions are bad; this is not the area which is famine-stricken or drought-a'lected. Why are you not holding elections to the Broach Parliamentary constituency ? In Barpeta constituency elections were held.

There is a vacancy after the demise of late Mr. Krishna Menon in Kerala, but the elections have been put off. If you have got faith in democracy, then wherever there is a vacancy, it is the duty of the Election Commission and the Government of India to see that elections are held as early as possible. This morning, there was a protest and a walk-out because the Delhi Corporation has been superseded. It has been taken over by the Government. In the normal course, if they had allowed the Delhi Corporation to function, then it

[Shri Veerendra Patil] was incumbent on the part of the Government to hold elections in the month of May. They are afraid to hold the elections. They are afraid to go to the polls and to face the people. That is why this excuse came very handy to them. Since a stable Corporation was not possible, they have taken over. Now, they can put off the elections for one or two or three years. That is why 1 say that the party in power is losing faith in democracy. That is not a healthy sign. An agitation is going on. Hon. Members on the other side know that when agitations start, they become violent because they have had the experience of such an agitation launched by Nav Nirman Samiti. We should not give any scope for any party or organisation to launch agitation. Otherwise, the ruling party will be creating an atmosphere in the country that they can understand the language of agitation onTy. We should not give any such scope to any political party. Therefore, I join with my other colleagues in demanding that there should not be any delay in holding the elections and the elections should be held as early as possible. When there is any agitation, they should not give any scope to continue the agitation.

I want to make out one or two pornts. I find in the budget that a Harijan Development Corporation is going to be established. But they have not provided any funds at all. What is that Corporation going to do if there are no funds at all ? 1 want to know from the concerned Minister for what purpose this Corporation is proposed to be set up and what is the amount that has been provided or is going to be provided for this purpose. Is it only a political gimmick to attract the Scheduled Castes people when the election takes place and to tell them that such a Corporation is going to be set up for their amelioration and a lot of funds are going to be provided ? I do not wish to take much time of this House because what 1 find today is that so far as famine is concerned, famine relief is entirely manned by bureaucracy. There is no Town Panchayat. There is no District Panchayat. There is no Municipality. There is no Assembly. There is no popular government. I want to know who is manning these reiief operations. If there had been no Assembly, but there were District Panchayat or Town Panchayat or Municipality elected by the pecple, I would have understood. All these institutions have been supei seded and taken over by the officer and the entire famine relief work is being manned by the bureaucracy. That is why there is so much of resentment, discontentment and dissatisfaction that is growing and the people are suffering. They are allowed to suffer like that. So, in the interest of democracy and the people who are put to untold suffering, I would like to make an humble appeal to the Government to see that popular Government, popular District and Town Panchayats and Municipalities are installed in office as early as possible. With these few words, I conclude my speech.

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Budget for Gujarat makes an estimate that after the Revenue and Capital Accounts are taken together, there will still be a deficit of Rs. 2.37 crores and, according to the State Government's own admission, the State Government would have overdrawn its cash balance by Rs. 6.57 crores at the close of the current year. As a result, you will find that in addition to the heavy withdrawal of cash balance, in addition to the deficit in the coming Budget, the State Government will have no recourse except to have further taxation on the people. Sir, the State Plan for 1974-75 consists of resource from the State and the Central assistance, Unfortunately, the Central assistance for the State Plan for 1975-76 has been assumed at Rs. 32.17 crores which is of the same order as that of the current year. In fact, if you take into account the increase in prices, in the coming year's annual plan, the Central assistance for tho State will be substantially lower in real terms compared to the Central assistance of the current year. Sir,

you will also find that in the statements provided by the State Government, certain moneys have been provided for drought relief which is one of the major problems of the Gujarat State today. In addition to the Finance Commission's non-plan allocation of Rs. 4.55 crores, a provision has been made in the Budget of hardly Rs. 11.60 crores. Of course, this is in addition to the special provision of Rs. 15 crores for relief works. But, I would like to point out that according to an unofficial estimate, the amount required for relief will be anywhere near Rs. 100 crores. Rs. 100 crores will be required immediately for drought relief in Gujarat. And, in fact, there is another unofficial estimate which puts it around Rs. 200 crores. So, against this estimate of Rs. 100 crores or Rs. 200 crores of real need regarding the drought assistance, a provision has been made of Rs. 11.60 crores, plus a special provision of Rs. 151 crores. Therefore, it is very clear that the Gujarat Budget makes only a very paltry provision for drought relief which is one of the most important problems facing Gujarat today. Now, unfortunately, despite the serious drought, where there were starvation deaths, where even the mothers had to sell their children, where the Adivasi people had to live on the barks of the trees— converting the bark into a paste and eating it— and despite such severe conditions, the Central Government has been pleased to give only this small amount of Central assistance which is, in money terms of last year, unfair and unjust to a State like Gujarat. Malnutrition has led *to* epidemics in several parts of the State. In fact, in May and June, the Administration will have to face the problem of providing drinking water *to* a large number of villages. No provision really exists now. All this comes in the backdrop of the Presidential rule in Gujarat which has no relation to the needs and aspirations of the people.

Sir, according to a survey made recently by the Institute of Political Science, under the guidance of its Director, Prof. K. S. Mawani, and assisted by Mr. Yeshwant Janani, to elicit public opinion about the anticipated elections, the survey has revealed that 70 per cent of the voters of Gujarat want elections to be held right now, and 75 per cent of the people want popular ministry to be installed immediately. Sir, this is the result of an objective study made by the Institute of Political Science which comes out very clearly that 70 per cent of the people do not want the Presidential rule. On the contrary, the Central Government still thinks that they should extend the President's rule, thereby butchering democracy in Gujarat. Gujarat is highly anti-democratic Perpetuating President's rule in and unjust on the part of the Government. Sir, the Home Minister, Shri K. Brahmananda Reddy, defended the Government's decision to extend the President's rule in Gujarat and he said in a statement made on February 27 that the President's rule in Gujarat is being extended on the ground that elections would interfere with relief operations in that drought-hit State. This was his defence and he wanted postponement of the elections on the plea, on the completely indefensible plea, that elections would come in the way of drought relief. Sir, what are the realities of the situation ? During the President's rule the amounts spent on drought relief have gone down the drain and have been pocketed by contractors, by officials and by various other types of corrupt people and there is nobody to put popular pressure on the administration because it does not exist.

Sir, let us look into the relief operations. A report which appeared in *The Stat* of Calcutta, dated the 19th February, 1975, says and I quote :

> "All the political parties, including the Congress—Sir, I underline the words 'including the Congress'—criticise the Government's relief operations. Many people in the scarcity areas feel that a popular Ministry is better equipped to deal with their problems".

[Dr. K. Mathew Kurian]

Here is a statement appearing in the press, a report in *the Statesman,* conclusively asserting. that all political parties, including the ruling Congress, are unanimously criticising the relief operations under the President's rule. And, the statement goes on say that:

> "A team of experts who visited the drought-hit areas last year reportedly found that the State's claims were exaggerated. The people in some affected areas have challenged official claims that the number of relief works and wages provided are adequate".

Sir, on the contrary, this publication of the Government of Gujarat "Twelve Months of President's Rule in Gujarat" makes all kinds of tall claims, which have no relation to what actually happened in the field.

Sir, during this President's rule we find autocratic, semi-fascist attempts to curb all agitations. I have got here, Sir, one interesting case. Sir, this is the case of a journalist. Sir, this is reported in *The Indian Express,* New Delhi, dated the 9th August, 1974. I quote.

> "Some 25 journalists were beaten up by the police outside the house of Mr. H. C. Sarin, Adviser to the Gujarat Governor, here this morning."

Why did the police beat up the journalists? Because the journalists had gathered there to see Mr. Sarin and to protest against the police harassment of a journalist. Just because the journalists went infront of Mr. Sarin's residence to protest against the harassment of journalist, police terror was unleashed against the journalists in Gujarat; that is what is happening.

Sir, similarly, I would like to bring to ycur attention another important matter. Sir, in the Additional Accountant General's Office in Rajkot certain employees were arrested and the Finance Minister made a statemem in the Lt>k Sabha on 22nd August, 1974, where he said:

> "The strike affected about 20 Audit :>nd Accounts Offices in the country. In the offices at Rajkot and Gwalior there were cases of serious intimidation and violence by some striking employees with the consequence that they were arrested by the police."

Sir. in fact this statement of the Finance Minister in the Lok Sabha is absolutely untrue and I have got information to show that the employees in the Additional Accountant-General's office in Rajkot were arrested tor one hour because of the one-hour demonstration on 7-6-1974 between 4.30 and 5.30 p.m. and not for participating in the strike on 10-5-74. The demonstration was also peaceful as can be seen from the charge-sheet given by the police itself. Therefore, I am trying to show that even the charge-sheet of the police does not show any violence or intimidation but the Audit Department gives a brief to the Finance Minister and he reads it out in Parliament which is completely contrary to what the real facts are. 1 would therefore request the hon. Finance Minister through the Deputy Minister who is present to verify the facts. *{Time bell rings)* T will take only two or three minutes more and complete. In the Audit Department throughout the country and in the Rajkot office there has been unfettered use of DIR, unfettered use of police to intimidate the working class.

Lastly, Sir, I come back to the main point, namely, why all these are happening. Drought relief is not adequately met, there is nobody to demand adequate assistance from the Central Government consistent with the demands of the State. Police power has been unleashed against tournalists, against middle-class employees and against Audit Department employees because somebody who has no direct relation with the people rules in Gujarat.

Sir, what is happening today ? Today in this House a question was raised regarding superseding of the Delhi Municipal Corporation and the Home Minister

was defending it in a most shameful manner. At the same time, in Kerala for instance, the Kerala Government has lost its majority. Six to seven Muslim League MLAs have ceased attending the Assembly. They boycotted the Assembly and as a result, the Congress-led Government, the Achuta Menon Government which is propped up by the Congress has lost its majority. But the Government in Delhi wants to protect it and Borronh hat. already come out for giving. .. (Interruptions) ... a lot of incentives to the Muslim League. They are still fishing in troubled waters. You are a minority there, if the Central Government wants to take a consistent stand, let them take a principled stand on this. Let them not have double standards. It has one standard for Gujarat, another for Bihar and yet another for Delhi. Kerala was the first State where the elected Government of Shri EMS Namboodiripad had a solid majority of one in the Assembly for the entire period of its existence and ii was dismissed by the then Congress President who is the Prime Minister of today, Mrs. Indira Gandhi. Sir, this is the attitude of the Central Government that even when a State Government has a majority as proved in the case of the United Front Government of 1957-59, it is dismissed by the Central Government. Today the Delhi Municipal Corporation is superseded. Elections are not being held in Gujarat. Therefore, I demand that the Central Government should change its anti-democratic, semi-fascist attitude, they must avoid double standards and have a principled stand on all these questions. Otherwise the rising tide of revolution against the Central Government which is today visible throughout the country will come and give a bigger jolt and the Central Government will have to face the consequences.

SHRI K. N. DHULAP: Mr. Vice-Chairman, Sir, if one goes through the report that has been given to us on this 12-months President's rule in Gujarat and one tries to read between the lines it will appear this President's Rule is a boon to the people of Gujarat. Everything that has been done by the Government during this Rule for one year is in the direction of dealing with every situation very effectively and nothing has been left to be done by the popular Government that is to come in Gujarat. Therefore, I would request the hon. Minister who is going to reply to this debate that she should give a clear-cut assurance to this House as to when elections are going to be held in Gujarat because the condition of Gujarat, created by unprecedented drought, is such a serious one that not only the people of Gujarat but the people of Maharashtra are also going to suffer. Gujarat is so adjacent to Maharashtra that whatever happens in Gujarat has serious repercussions on the economy of Maharashtra and on the people of Maharashtra. Therefore, elections should be held immediately. At present the President's Rule is not the rule of the people. The present administration is not in a position to deal effectively with the serious situation which Gujarat has to face. So far as doing something about the drought, it appears that the condtion is going from bad to worse. Billions of cattle died because of the non-availability of fodder in Gujarat. The pipeline of supply of foodgrains is not properly working and lakhs of people are on the verge of starvation. So, Sir, the only wish that [can express before this House is that if there is a popular government then the people can go to the representatives and get their grievances redressed once for all. The present situation in Gujarat is such that it calls for immediate elections and, therefore, 1 would request the hon. Minister to give a categorical assurance to the House that the elections would be held as early as possible.

There are also certain important issues to which I will refer. During this President's Rule the atrocities committed on Harijans have increased. Take the case of Bhupgarh near Rajkot and then Chun-dilia incident near Ahmedabad also Ran-malpura where two persons were killed and several injured. There are so many other incidents which took place during

[Dr. K. N. DhulapJ

this regime and no effective steps have been taken in this direction.

As far as tribals are concerned, in this resume they have referred to the formation of a Tribal Development Corporation for which only Rs. 15 lakhs have been sanctioned. What the Tribal Development Corporation is going to do with this amount for the welfare of the tribals "and amelioration of the backward class I do not understand. So many tall claims are made by the Governor in this resume which has been given to us but I must say that there are lakhs of people living in villages, particularly in tribal areas who are not getting their dues and particularly in this drought situation they are facing a very critical situation.

As far as smuggling activities are concerned, they have increased during the Governor's Rule. The township of Vapi is the centre of all anti-social activities. The trains going from Vapi to Bombay are ridden with people who are dealing with the smuggling business. And Diu and Daman are the spots from where the smuggled goods coming from Dubai and Kuwait enter the area. That area is ridden with such people. If no steps are taken, this thing is going to increase—and that is having a very bad effect on the administration of the State of Maharashtra. Therefore, Sir, these smuggling activities during the Governor's regime have increased enormously and no effective steps have been taken by the Central Government to curb these activities. As far as Daman and Diu are concerned, these are two spots which are at present under the Goa Administration. These two areas, Daman and Diu, should go to Gujarat, because they are near Gujarat and the demand of the people from that area is that they should be merged with Gujarat. Sir, Nagar Haveli, which is governed by the Central Government, should go to Maharashtra because people living there are predominantly Marathi-speaking people. All tall claims are made by the Governor during his regime for one year. 1 would urge upon the Government to have better administration, efficient administration, and a clean administration. As has been referred to by my friend Makwana here, the President's Rule has dealt with the drought situation very effectively and elections should not be held. This President's Rule, according to him, may be efficient, may be clean, may be more according to the needs of the people. But that does not mean that it should substitute the popular Government. Let there be a popular Government and let the people feel that they arc governed by their own people and not b> autocrats.

With these words, I conclude.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, I would only say a few words at the fag end of the day.

श्री राजनारायण : खूब बोलो।

SHRI BHUPESH GUPTA : *I* cannot keep pace with you, either in size or in thoughts. Now, Sir, Gujarat is under President's Rule. Unfortunately, the Government is not taking steps within the framework of improving the conditions of the people in some cases; on The othei hand, we find the attitude is not good. Now, Sir, 1 am a little apprehensive be cause 1 do not know what the Central Government is thinking—I do not have anything to say against the hon'ble lady sitting in the state of meditation.

Sir, Gujarat has got some industrially developed cities like Ahmedabad. Otherwise, it is not industrially a very developed State. 1 hope Mr. T. A. Pai and Mi. Subramaniam will not take advantage of the President's Rule to try their tricks in Gujarat. This is one point that I would like to say because they are around and very active—these two are very active in forcing certain policies which are even not properly discussed with the Government. They are trying to drive the position ti> a point where the Government will have no alternative but to sign on the dotted lines according to their wishes, wishes of Mr. Subramaniam and Mr. T. A. Pai. Sit,

Gujarat is one of the States where we have always to collect arrears—and I think the collections should be made. But can they make collections of income-tax arrears when they patronise the income-tax evaders and dodgers—not only in Gujarat, but in other parts of the country ? 1 have in mind Mr. Birla aVid the Birlas. Here, Sn, today in the Hindustan Times, a Birla-owned paper, there is a news-item on the very first page. It says : "Ganesh in conflict with the Party". Let them quarrel in their Party; that is none of our business. But what he said otherwise is significant. T. A. Pai started this policy of so-called "national sector", which is in fact a policy of surrender of public sector to the monopoly capital, this policy is naturally very much supported by the 'Hindustan Times' and in fact in one of the editorials written only on the 22nd of March, it said :

> "It is a pity that both Mr. Subra maniam and the Industries Minister, Mi. T. A. Pai. have become targets for Communist vilification . . ."

Sir. I would normally like to bring a privilege motion; we have not vilified; this Birla paper is vilifying.

> "... Neither of them, nor the Government as a whole, should be cowed down by such attacks and it is unfortunate that Mr. Subramaniam and other official spokesmen have been as diffident as they have in defending the concept of the so-called 'national sector', a new term for the joint sector which in turn has long existed in the country in the sense ct mixed companies with both State and private participation. There is no need to be apologetic . . ."

Now, here again the paper writes about the tax evasion :

> "A number of raids have admittedly been carried out and a substantial number of alleged offenders have been arrested. But what does cause concern in the apparent slow progress in prosecuting .. ."

But what about the Birla cases ? Why are the Birlas allowed to freeze all their cases by injunction and writ petitions ? How long does it take a writ petition to be disposed of ? And we find the Birlas have succeeded in getting them postponed even for a year. Now this is their attitude. 130 cases have been pending including the wealth tax cases. No solution. What happened to the Sircar Commission ? I do not know where Mr. Sircar is. But the Sircar Commission is a sleeping commission because big monopoly houses like the Birlas are before them. Nothing is being done. Who gets it, we know very well. Sir, Mr. K. K. Birla has been daily praising this Government. Not a day passes without Mr. K. K. Birla showering praises on Shrimati Indira Gandhi and her Government. I think Shrimati Indira Gandhi would feel a little embarrassed when so much praise comes from Mr. K. K. Birla. When we and others praise her, I can understand . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) : Bhupesh Babu. we are discussing Gujarat.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradeshl : Do you want them to praise you ? That is what you say.

SHRI BHUPESH GUPTA : What I want to do, I do not want to learn from Jana Sangh. I will come to it when we come to the other debate. And now, Sir, we may do it but when Mr. Birla does, well, one should feel a little embarrassed.

Now here, Sir. What does the 'Hindustan Times' says'.' 'Ganesh in conflict with Party". Today's 'Hindustan Times' says it. The entire write-up is an attack on Mr. Ganesh because he has made a speech in a seminar in Madras where he expressed his opinion against the so-called national sector which is now, as I said, a sell-jut of the public sector to the private sector. And in this article, this 'Hindustan Times' is directly provoking by referring to Mr. Dharia's case. I do not know why they have referred to it. They are directly

[Shri Bhupesh Gupta,]

provoking that Mr. Ganesh should be thrown out of the Government. Now people say it is the internal affair of the Congress Party, the 'Hindustan Times' here is attacking the Minister simply because he stands by the public sector and does not speak favourably for the so-called concept of joint sector . . .

SHRI RAJNARAIN : Is there anything in 'Patriot'?

SHRI BHUPESH GUPTA: 'Patriot you read. Sir, apart from doing it, here it says :

"In his Madras speech, Mr. Ganesh has virtually questioned the Union Cabinet's decision and has said that the Indian National Congress is the only 'right body' to decide whether any change in the concept is necessary. While Mr. Mohan Dharia had to go out of the Council of Ministers for his open criticism of the Government's failure to implement the policies of the Congress Party, Mr. Ganesh is now virtually taking up the position that the Union Cabinet has no right to throw open the equity of public sector companies to the general public."

श्री राजनारायण : मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है। श्री गणेश चापलूसी करें कांग्रेस की और इन्दिरा जी से जा कर मिले...

अगर इन्दिरा के केबिनेट में रहकर इंदिरा की पोलिसी के विरुद्ध बोलना ठीक है तो भूपेश गुप्ता जी, आप इंदिरा जी से कहिये कि गणेश को केबिनेट में रखो। धारिया को जब निकाला गया... (*Interruption*) । मैं पाइन्ट आफ आर्डर पर बोल रहा हूं। मैंने धारिया से कहा कि... (*Interruption*) । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री गणेश को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का हक है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : यह इनकी पार्टी का आन्तरिक मामला है। श्री भूपेश गुप्ता जी, अब आप समाप्त कीजिये।

SHRI BHUPESH GUPTA : He has not understood it. I am not for or against Indiraji.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAO-DISH PRASAD MATHUR): Now, you finish. You wanted only five minutes.

SHRI BHUPESH GUPTA: But you have given three minutes to him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) : Please finish.

SHRI BHUPESH GUPTA : I am saying this and he also supports me. In maintaining the public sector he do-es not support the view that monopoly capital should be given a share. All that I am pointing put here is Mr. Birla, on the one hand, is propagating his theory and, on the other hand, is trying to make out as if to criticise him. is criticism against the Government's policy. I do not take that point of view.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): The Birlas have made up with Shrimati Indira Gandhi fully and completely. Otherwise, Mr. Verghese would not have been sacked.

SHRI BHUPESH GUPTA : It is all right.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Why do you not support Mr. Verghese ?

SHRI BHUPESH GUPTA : It is a different matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): This is Gujarat Budget, not the Birlas' budget.

SHRI BHUPESH GUPTA: Gujarat is the seat of capital. If yoai do not look after your monopolists, you do not look after Gujarat. Therefore, by analogy I am going it. It is very tricky. This is the kind of thing going on. I am asking her not to try these tricks in Gujarat. This is all. She is nodding favourably, I think. The lady is not certainly rejecting my suggestion. This *is* all that I have to say. ..

SHRI N. G. GORAY: You have always misunderstood ladies.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am very sorry for my friend, Mr. Goray. He has been subjected to ladies' protests too much, I believe, but I sympathise with him. Now, Sir, all I say is that this should not be done.

Finally, one point. Today I hear that a decision has been taken by those who want to start a JP type movement in Gujarat that MPs will not be allowed to enter Gujarat. You will not be allowed to enter Gujarat. . .

SHRI RAJNARAIN : Congress MPs and CPI.

SHRI BHUPESH GUPTA : This kind of thing should not happen. That MPs should be made to resign at gun-point, that MPs should not be allowed to go to a State, whether somebody likes it or not. should not happen. I think Mr. Rajnarain and Mr. Goray and others will not support that kind of thing.

DR. RAMKRIPAL SINHA (Bihar) : Mr. Ghafoor does not allow Mr. Rajnarain to enter Bihar. What do you say to that ?

SHRI BHUPESH GUPTA : He knows Mr. Rajnarain is such a guest that it is difficult to find a guest-house for him. Mr. Ghafoor does not have arrangements for keeping such a man.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: You have a guest-house in Moscow.

SHRI BHUPESH GUPTA : At any raic our Bihar friends are sitting here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Please finish.

SEPRI BHUPESH GUPTA : As far as I am concerned, I say this is a very wrong thing. I deplore this kind of attitude on the part of those who are starting the movement in Gujarat or propose to start it. Whatever their movement is, I do not know why it should be like that. Today you may be in power and tomorrow another person may be in power. Tomorrow the Congress party may declare that other MPs belonging to the opposition will not be allowed to come. We must not set this standard. Therefore, I strongly oppose such a thing. I do hope the people of Gujarat will not go by this kind of thing. I say finally the Government should think of taking over some of the big industrial concerns there. At least they should make preliminary studies when Gujarat is under Central rule, so that we can think of improving the conditions in Gujarat. One word more and I finish. This is non-controversial. Women live in extremely bad conditions.

I am sure Mr. Rajnarain who is a very controversial figure will not say anything.

Sir. literacy among women there does not exceed three per cent. In many ways they are subjected to all kinds of social and economic disabilities. I hope that the Government in this International Women's Year will take some steps with a view to ameliorating the status of women of Gujarat. After all. Gujarat is a land which is full of great traditional achievements in the freedom struggle a.nd otherwise also, and 1 hope that in the matter of employment, in the matter of education and otherwise also the Government would pay special attention to the women of Gujarat. Sir, through you, I do urge upon the Central Administration there, upon the Governor and the Advisers who are running the administration there, that they should go into the question of the problems of women. A memorandum has been submitted in this connection before them by the various women's organisations and they should take some measures with a view to uplifting the women socially and politically in the life of the State.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : I would like to extend my thanks to the hon. Members who have participated in this discussion.

[Shrimati Sushila Rohatgi]

Sir, you will forgive me if I say that I thought the musical voice of Shri Bhupesh Gupta had attracted the Chair and other Members. Therefore, he had the privilege of discussing anything under the sky except Gujarat. I am very happy to her what he said about the status of women.

श्री राजनारायण : इन्दिरा गांधी की उनके ऊपर विशेष कृपा है ।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI :%m शायद इन्दिरा जी के ज्यादा नजदीक हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा ।

Sir, when any Budget is taken up, we are prepared to hear the political ideologies of all the political parties also. But I was a little taken aback when the great economist, Dr. Kurian. used really strong words. Whether he really subscribes to 50 per cent of what he really said, I do not know. Sir, before going into detail, 1 would say that I cannot understand why so much of polities has been injected into the Budget. I would like to say that the Oppo-ition Members have more or less accused the Government as if we are really responsible for having brought about this Budget before this House. I would only urge upon them to go back by a year and see what were the conditions. Was it not the Opposition alone which said that there should be the dissolution of the Assembly ? If there had been that Assembly, that would have been the correct forum where the Budget could have been discussed. It is unfortunate that the Budget has to be discussed in this House. The absence of the Assembly was due to the attempts of the Opposition. Therefore. under the circumstances, I think that is a very wrong charge, allegation, and it has been certainly vindicated by facts.

Another thing is this. Sir, T would ask my esteemed friend, a senior person from my State. Mr. Rajnarain, who is a known all-India figure, whether he would be justi fied in saying that Congress Members or others...

श्री राजनारायण : 23 करोड़ की बात कहिए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : 23 करोड़ पर जाने से पहले मैं सिद्धांत की बात करती हूं केवल 23 करोड़ ही नहीं, जिसके ऊपर सारा लोकतंत्र है, वह चाहे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हों चाहे आपकी तरफ से हों, जो चुन कर आए हैं ...

श्री राजनारायण : लोकतंत्र के बारे में अलग से बात कर लें तो अच्छा हो । (**व्यवधान**)

श्रीमती सुशीला रोहतगी : वह बड़े सम्मानित सदस्य हैं, मैं उनका बड़ा आदर भी करती हूं । मगर जहां तक लोकतंत्र की बात है इसमें हम लोगों की अलग अलग परिभाषा है ।

मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि जो लोग वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में यह कहते हैं कि उन्हें वहां पर प्रवेश नहीं करना चाहिये, यह बात कहां तक लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल है ?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, श्रीमती सुशीला जी ने हम से एक प्रश्न किया है और यह मेरा कर्तव्य हो जाता है कि उसका जवाब दूं । मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का मतलब यह है और मैं एक ही वाक्य में कह देना चाहता हूं ...

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : आप लोकतंत्र की बात मत करें क्योंकि आप तो धक्कातंत्र की बात को जानते हैं ।

श्री राजनारायण : लोकतंत्र के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि बाई दि पीपुल, आफ दि पीपुल और फार दी पीपुल । इसमें कांग्रेस के जो एम०पीज० हैं, वे फार दी पीपुल नहीं हैं । They are for their family and for their individuals. Therefore, the people have got every right to check them, to remove them.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, मैं इस चीज पर नहीं पड़ूंगी क्योंकि उनकी जो भाषा है वह स्पष्ट नहीं है । मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि जनता की राय इस वाक्य के विरुद्ध नहीं है । जब तक राय बदल नहीं जाती एक

खुले चुनाव द्वारा और दूसरे लोग हमारे सांत प्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आ जाते हैं, तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

मान्यवर, दूसरी चीज यहां पर जो आई है वह इलेक्शन के बारे में आई है। यह सही बात है कि वहां पर इलेक्शन होने चाहिये और जल्द से जल्द होने चाहिये। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने सारी तैयारी कर ली है। जैसाकि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर इस समय गंभीर परिस्थिति है और अगर इस समय इलेक्शन होते हैं, तो जो लोग वहां पर राहत कार्यों में लगे हुए हैं उनको इलेक्शन के काम में डाइवर्ट करना होगा इलेक्शन की सारी तैयारी के लिए क्योंकि इलेक्शन एक दिन में नहीं कराये जा सकते हैं। इस काम के लिए महीनों से तैयारी करनी पड़ती है। अगर वहां से लोगों को इस कार्य में लगा दिया जाता है तो जो राहत के कार्य हो रहे हैं उनमें बाधा पड़ेगी। वे लोग जो कार्य कर रहे हैं, वह एक मानवीय कार्य है और अगर उन लोगों को इस कार्य से हटा दिया जायेगा और दूसरी तरफ लगा दिया जायेगा, तो इसका डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली सात लाख लोगों पर असर पड़ेगा। जो लोग इस समय अकाल से पीड़ित है, उन लोगों को अपना वोट डालने का अवसर मिल सकेगा या नहीं, वे लोग वहां पर पहुंच सकेंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है। इसके साथ ही साथ जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं वे भी अपना वोट डाल सकेंगे या नहीं, यह कहना कठिन है।

मान्यवर, इलेक्शन होने चाहिये, यह एक प्रश्न है, जिस पर हमें गंभीरता के साथ विचार करना चाहिये। हमें यह भी विचार करना होगा कि आगे जो महीने आने वाले हैं अप्रैल और मई के, उनमें वहां पर भीषण परिस्थिति हो सकती है। इसलिए जिन लोगों को इस समय जटिल समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो इस कार्य में लगे हुए हैं, उनको वहां से हटाकर इस काम की तैयारी के लिए हमको लगाना होगा।

मान्यवर, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया था और मेरा ख्याल है कि इस बारे में सब को मालूम होगा कि सारी परिस्थितियों को सामने रखकर वहां पर इस वक्त इलेक्शन कराना कहां तक सही होगा और कहां तक न्याय संगत होगा ? इसलिए जब तक वर्षा नहीं हो जाती है तब तक उस समय तक कम से कम इलेक्शन कराना उचित नहीं होगा। अब कब स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, कौनसा महीना होगा जब वहां पर इलेक्शन कराये जा सकेंगे, इन सब चीजों पर हम विचार कर सकते हैं। यह बात कभी भी नहीं कही गई है कि वहां पर इलेक्शन नहीं होने चाहिये क्योंकि इलेक्शन की अपनी एक पद्धति है और उसको सब ने स्वीकार किया है। यह बात तो हमारे राजनारायण जी भी स्वीकार करते है और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस चीज को अच्छी तरह से स्वीकार किया है।

मान्यवर, मैं पांच मिनट और लूंगी। जो हमारे वहां पर गांव है, जो अकाल पीड़ित और अभाव-ग्रस्त घोषित किये गये हैं, उनकी संख्या 12,146 है जहां पर इस समय राहत का कार्य चल रहा है। जहां पर प्रोटेक्टिव वर्क चल रहा है उन गांवों की संख्या मिलाकर 4,725 है। इस तरह से वहां पर योजना का कार्य चल रहा है और इन गांवों की संख्या करीब पौने पांच हजार है। इनमें जो लोग लगे हुए हैं उनकी संख्या करीब 7,26,798 है यानी करीब सवा सात लाख लोगों की बड़ी संख्या इसमें लगी हुई है। जिन लोगों को कैश डोल दिया जाता है उनकी संख्या करीब 47,215 है। जहां पर गांवों में पानी की कमी है, वहां पर पानी देने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के 225 गांव हैं जहां पर टेंकरों और बुलककार्टों द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। इस तरह का कार्य वहां पर बराबर जारी है।

इसके अतिरिक्त वहां पर पशुओं के लिये चारे की भी दिक्कत । इस तरह से वहां

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

पर पशुओं को कष्ट हो रहा है और 621.43 लाख मन घास और स्ट्रा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

आज गुजरात में जो कष्ट लोगों को उठाना पड़ा है उसके लिये हम लोगों की सहानुभूति है। सहानुभूति तो हमारी है ही, वहां की जनता को बधाई भी है कि उसने इन कष्ट को बड़ी वीरता और हिम्मत के साथ सामना किया है। इसके अतिरिक्त वोलंटरी एजेन्सीज के द्वारा जो कार्य हो रहा है यह ठीक है कि वह सब्सीडाइज किया जा रहा है, मुफ्त तरीके से भी किचन चलाई जा रही है। श्री वीरेन्द्र पाटिल ने कहा कि गवर्नर के राज्य में उनकी सफरिंग मिटीगेट नहीं की गई है। यह सत्य से परे है। यह जरूर है कि जो भी कार्य किया जाता है उसमें सुधार का स्कोप रहता है। इसके अतिरिक्त यह भी है कि स्टेट गवर्नमेंट ने 100 नए टैंकर खरीदे हैं। 348 पहले से ही हैं। इसमें उन्होंने 100 और जोड़े हैं जिससे लोगों का कष्ट और न बढ़ सके। इसके अलावा 15 मार्च से एक न्यूट्रिटिव डाइट भी दी जा रही है जिन पर 40 पैसे खर्च पड़ता है। इससे 4 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा, पर यह अवश्य है कि लोग कष्ट में हैं उन को तीन रुपए के अतिरिक्त न्यूट्रीसन भी साथ साथ मिल जायेगा।

कई माननीय सदस्यों ने हरिजनों और आदिवासियों के प्रश्न को भी उठाया, जो उचित भी था। इसके विषय में मैं दो मिनट अवश्य लूंगी। गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल रूल के अन्तर्गत हरिजन और आदिवासी भाइयों के लिये कई कदम उठाए इनको अच्छी तरह से कार्यान्वित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। एक हरिजन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जो गजटेड पोस्ट्स के लिये उनका रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया गया है 5 से 7 हरिजनों के लिये और 10 से 14 आदिवासियों के लिये। यह भी निश्चय किया गया कि सब-इंस्पेक्टर्स के केस में उनका रिजर्वेशन रखा जाय। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रियायतें देने का फैसला किया गया है। जो स्कालरशिप्स दी जाती है उनकी राशि 10 से 25 रुपए कर दी गई है। इनकम लिमिट भी 6000 से 7200 कर दी गई है। स्टाइपेन्ड 45 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भूमि के ट्रांसफर के बारे में इंस्ट्रक्शन दिये गए हैं कि जो ट्रांसफर वगैरह आदिवासियों की भूमि के थे उनको एनुल कर दिया जाय।

श्री राजनारायण : क्या ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: The Government has issued instructions to Collectors to annul transfers of land belonging to Adivasis and to restore their possession to them.

यह प्रश्न उठाया गया था। मैंने सोचा कि मैं उसका स्पष्टीकरण कर दूं।

पावरलूम्स का भविष्य में जो एलाटमेंट होगा उसमें से 50 प्रतिशत हरिजन और आदिवासियों के लिये पहले से रख दिया गया है। एक डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाने का भी विचार है जो उनकी आर्थिक प्रगति के सम्बन्ध में कदम उठाएगा। यह भी है कि जितनी कमेटीज और पेनल्स बनेंगे उनमें हरिजन और आदिवासी भाइयों का प्रतिनिधित्व अवश्य होगा।

इसके अलावा अनटचेबिलिटी हटाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। जो लोग अनटचेबिलिटी ओफेन्डर्स डिक्लेयर किए गए है उन लोगों को किसी पैनल में सम्मिलित नहीं किया जायगा, ऐसा निर्णय भी लिया गया है। जो पुलिस आफीसर्स हैं उनको कहा गया है कि अनटचेबिलिटी के कार्य के संबंध में उनको परफोरमेंस रिपोर्ट मिलेगी और उसके आधार पर उनका प्रमोशन किया जायगा। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनस दिए गए हैं कि जितने आफीसर्स हैं ऊपर से नीचे तक वे अनटचेबिलिटी हटाने में विशेष रुचि लें और उसके लिए हर प्रकार का प्रयास करें। रमालपुर की घटना के संबंध में, जो कि सारे सदन को मालूम है, प्यूनिटिव टैक्स भी लगाया गया है।

यही नहीं, 38 गांवों में जहां प्रिवेंशन आफ अनटचेबिलिटी ऐक्ट का किसी प्रकार से विरोध किया गया था और उस के अनुसार जहां काम नहीं हुआ है उन गांवों की पंचायतों की ग्रान्ट इन ऐड रोक दी गयी है ताकि और दूसरी गांव पंचायतों पर भी इस का असर पड़े और यह काम वहां शीघ्रातिशीघ्र हो सके । इस के अतिरिक्त जो इंसेटिव कैश एवार्ड की स्कीम थी और जिस में 500 रुपया दिया जाता था उस को बढ़ा कर 5000 कर दिया गया है । इसी दृष्टि से और भी कार्य किये गये हैं कि जिस से हरिजन और आदिवासी भाइयों को अधिक सहूलियत मिले । हरिजन डेवलपमेंट कारपोरेशन के लिये भी यहां जिक्र आया था और उस के बारे में अभी कोई चीज डिटेल में तो निश्चित नहीं हुई है लेकिन उस को स्थापित करने का पूरा विचार है और इसीलिये उस के संबंध में घोषणा की गयी है । मान्यवर, बहस में बहुत से प्रश्न उठाये गये हैं अगर आप कहें तो एक एक लाइन में उन का जवाब दे दूं । जैसे स्टैपिल काटन के बारे में कहा गया कि वह काफी इकट्ठा हो गयी है । और सरकार उस के लिये कुछ नहीं कर रही है, उस को खरीदने के लिये कुछ नहीं कर रही है । उस के बारे में सरकार को पूरी जानकारी है और हमारे मंत्रालय उस पर हर पहलू से विचार कर रहे हैं और लेटेस्ट पोजीशन यह है कि उस की 15 से 20 हजार के बीच में बेल्स हैं जो अभी तक नहीं बिक पायी हैं । वैसे जितनी गांठे थीं उन का इंतजाम हो चुका है । नर्मदा वाटर डिस्प्यूट के बारे में जोशी जी ने कहा । यह ठीक है कि उस का जल्दी ही निर्णय होना चाहिए क्योंकि ऐसा होने से जो पानी बेकार जाता है वह बच सकेगा और साथ ही जहां पानी की कमी है वहां उस का उपयोग हो सकता है । लेकिन यह मामला ट्राइब्यूनल को गया है और दिसम्बर के बाद वह गुजरात के केस पर विचार कर रहा है । ख्याल है कि 9 मई तक गुजरात अपनी तरफ से अपने सारे पक्ष को उस के सामने रख सकेगा और उस के बाद मध्य प्रदेश अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा और आशा है कि यह चीज जल्दी ही तय हो जायेगी ।

कुछ एक माननीय सदस्यों ने सिक्सथ फाइनेंस कमीशन के बारे में कहा । यह सही है कि एक नीति के आधार पर उस का फैसला होता है और

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

The Sixth Finance Commission had recommended already for non-Plan expenditure on relief works a sum of Rs. 4.55 crores a year and a provision of Rs. 11.60 crores has been included in the Budget for 1975-76. Besides, the Budget also provides for outlay on relief works and a provision of Rs. 6.00 crores has already been made in the Budget for 1975-76 for the Drought-prone Area Programmes which will also help in the relief work and an expenditure | of Rs. 23.00 crores has already been incur-i red for scarcity relief work by the end of 1975. During 1974-75, the Government of India sanctioned an advance Plan assistance of Rs. 14.14 crores which is inclusive of about 4.25 crores for the Drought-prone area Programmes to enable the State Govt, to meet the scarcity situation. The Government has also sanctioned two or three short-term loans of Rs. 5.00 crores each for agricultural inputs like seeds, fertilizers, etc.

एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न भी उठाया कि कितनी भूमि हरिजन भाइयों को वितरित की गयी । मैंने उस के आंकड़े इकट्ठा करने की कोशिश की और इस वक्त तक जो मुझे पता चला है उस के अनुसार जो कल्टीवेबिल वेस्ट लैंड गुजरात में है और जिस को हाई प्राइरिटी दे कर डील किया गया है वह 4 लाख 20 हजार एकड़ भूमि ऐसी है कि जो उन में अभी तक डिस्ट्रीब्यूट की गयी है । तो यह मुख्य प्रश्न थे जिन को माननीय सदस्यों ने उठाया था और मेरा विश्वास है कि राजनीति को अलग रखते हुए और दूसरी चीजों को ध्यान में रखते हुए आशा है कि माननीय सदस्य इस बजट का स्वागत करेंगे और सर्वसम्मति से इस को पास करेंगे ।

श्री राजनारायण : गुजरात की सरकार ने जो 23 करोड़ रुपया स्पेशल आर्डर से वहां की जनता से वसूल किया है और पार्लियामेंट में उस को

श्री राजनारायण]

लाया नहीं गया, यह बात असंवैधानिक है । बिना पार्लियामेंट के एप्रूवल के 23 करोड़ रुपया गुजरात की सरकार ने कैसे वसूल किया। इस का उत्तर माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बाद में देंगे । उस को वह टाल गये हैं । कृपा कर इस का उत्तर आप दें। दो मिनट मैंने आपको कहा था मुझे दे दें । मैं एक मिनट लूंगा ।

श्री उपसभापति : आप एक मिनट लेंगे तो और भी लेंगे। देखिये आप खुद ही सोचिये ।

श्री राजनारायण : थर्ड रीडिंग में हमको एक मिनट दे दीजिए, इतना निवेदन है ।

श्री उपसभापति : थर्ड में बाद में देखा जाएगा ।

THE GUJARAT APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL 1975

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat for the services of a part of the financial vear 1975-76. as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

This Bill arises out of a sum of Rs. 268.02 crores voted by the Lok Sabha on the 21st March, 1975 and Rs. 144.27 crores charged on the Consolidated Fund of the State of Gujarat as shown in the 'Vote on Account' pamphlet circulated along with the Budget papers on the 5th March, 1975. These amounts have been sought to cover the expenditure for the first 5 months of the next financial year, i.e. April to August, 1975, in order to carry on administration of the State ot Gujarat, until the State's budget for the whole year is passed by the appropriate Legislature.

Sir, I move.

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I will put the motion to vote. The question is:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat for the services of a part of the financial year 1975-76 as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Tlie motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *and* 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

Chiiisc 1, *tiie Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE GUJARAT APPROPRIATION BILL, 1975

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Sir, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and apropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat for the services of the financial year 1974-75, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Bill is in respect of Supplementary Demands of Rs. 56.49 crores voted by the Lok Sabha on the 21st March, 1975, and an expenditure of Rs. 1.21 crores charged on the Consolidated Fund of the State of Gujarat for the year 1974-75. Full details of the provisions asked for have been given in the Statement of Supplementary